राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शनिवार, 31 जनवरी 2026
वर्ष 14, अंक 281, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

घर के अंदर खून से लथपथ मिला युवक का शव, आत्महत्या की आशंका..03

दिल्ली की सड़कों से बसें ग़ायब अपने मंजिल पहुंचने के लिए लोग परेशान..04

असमः 'मिया' मुस्लिमों पर विभाजनकारी टिप्पणी को लेकर सीएम के ख़िलाफ़ पुलिस शिकायत दर्ज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा 'मिया मुसलमानों' - यानी बांग्ला भाषी मुसलमानों - पर की गई विवादास्पद टिप्पणियों के बाद उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 'डर, बहिष्कार या नफ़रत फैलाकर' शर्मा 'भारतीय गणराज्य की बुनियाद को कमजोर करने के दोषी हो सकते हैं.' शांति और न्याय के कार्यकर्ता तथा लेखक हर्ष मंदर ने कहा कि उन्होंने मंगलवार (27 जनवरी) को दिए गए मुख्यमंत्री के सार्वजनिक बयानों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है. मंदर के अनुसार, ये बयान 'असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के खिलाफ नफरत, उत्पीड़न और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं.' मंदर ने बताया कि उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की प्रासंगिक धाराओं के तहत त्वरित कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. इनमें धारा 196 (समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य), 197 (राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल बयान), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए दुर्भावनापूर्ण कृत्य), 302 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से बोले गए शब्द) और 353 (सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयान) शामिल हैं. उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि उचित जांच की जाए और असम में चल रही विशेष पुनरीक्षण (एसआर) प्रक्रिया के दौरान भविष्य में इस तरह के बयानों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

मंदर द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, यह शिकायत दिल्ली के हौज़ खास थाने में दर्ज कराई गई है. हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायत पर आगे कोई कार्रवाई हुई है या नहीं. मंदर ने कहा कि मंगलवार को तिनसुकिया जिले के डिगबोई में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान शर्मा ने बांग्ला भाषी मुसलमानों को 'मिया' कहकर संबोधित किया और उनके उत्पीड़न, उनके खिलाफ भेदभाव तथा मतदाता सूची से उनके नाम हटाने को प्रोत्साहित करने वाले बयान दिए. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि शर्मा ने स्वीकार किया था कि उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान इस समुदाय के लोगों के खिलाफ शिकायतें और आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया था. बता दें कि शर्मा ने इसी हफ्ते मंगलवार को कहा था, 'कांग्रेस मुझे जितना चाहे गाली दे, मेरा काम मिया लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बनाना है.' उन्होंने लोगों से समुदाय को किसी भी तरह परेशान करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा था, 'रिक्शा में अगर किराया 5 रुपये है, तो उन्हें 4 रुपये दीजिए. जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, वे

असम नहीं छोड़ेंगे... ये कोई मुद्दे नहीं हैं।'

मंदर ने यह भी कहा कि 'हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा सीधे तौर पर मिया समुदाय के खिलाफ हैं,' और लोगों से मिया समुदाय को 'परेशान करने' की अपील की. उनका कहना था कि 'जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, वे असम नहीं छोड़ेंगे.' इससे पहले भी शर्मा कह चुके हैं कि उनकी सरकार 'मियाओं' को 'काबू में रखने' के लिए उन्हें 'परेशान' करती रहेगी. शर्मा ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर किसी भी विवाद से इनकार किया और विपक्ष के उस आरोप को खारिज किया कि फॉर्म-7 (जिसके जरिए कोई मौजूदा मतदाता किसी अन्य व्यक्ति के नाम को सूची में शामिल करने पर आपत्ति कर सकता है या मृत्यु अथवा निवास परिवर्तन के कारण अपना या किसी और का नाम हटाने का अनुरोध कर सकता है) का दुरुपयोग कर राज्य में वास्तविक नागरिकों को परेशान किया जा रहा है. शर्मा ने विशेष पुनरीक्षण का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि नोटिस केवल 'मिया' मुसलमानों को दिए जा रहे हैं, न कि राज्य के स्वदेशी समुदायों को।

गोलाघाट, असम में गुरुवार को शर्मा ने अपनी टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा कि जो लोग बांग्लादेश से आए हैं, वे खुद को 'मिया' कहते हैं और यह शब्द उन्होंने नहीं गढ़ा है. चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कर रहा है, लेकिन असम में विशेष पुनरीक्षण (एसआर) किया जा रहा है, जो नियमित अद्यतन जैसा है. शर्मा ने मंगलवार को कहा कि 'यह (एसआर) तो शुरुआती है. जब असम में एसआईआर होगा, तब चार से पांच लाख मिया वोट असम में हटाने होंगे.' चुनाव आयोग की ओर से अब तक मुख्यमंत्री के इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं आई है कि वे जानबूझकर आबादी के एक वर्ग को मतदाता सूची से बाहर कर रहे हैं. नफरत फैलाने वाले मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग का समय आ गया हैः सेवानिवृत्त न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) गोविंद माथुर ने एक बयान में कहा कि शर्मा के बयान धर्म के आधार पर नागरिकों को विभाजित करने का प्रयास हैं और भारत के संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं. उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'मुख्यमंत्री के रूप में शर्मा ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, और उनके शब्द राज्य की सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं.' उन्होंने चेतावनी दी कि डर, बहिष्कार या नफरत को बढ़ावा देने वाली भाषा संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती है और भारतीय गणराज्य की नींव को हिलाती है. जस्टिस माथुर ने यह भी कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा की गई सांप्रदायिक टिप्पणियां समाज में पूर्वाग्रह को सामान्य बनाती हैं और नफरत को बढ़ावा देती हैं, जिसका संवैधानिक लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है. उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकों को बांटने वाले नेता भारत की बहुलतावादी भावना और संघीय जिम्मेदारी के खिलाफ काम करते हैं. संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की उपयुक्तता पर सवाल उठाते हुए, जो निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों से हटकर आचरण करता है, जस्टिस माथुर ने कहा, 'भारत की ताकत एकता, विवेक और कानून के शासन में है, न कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में.' उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक नफरत फैलाना कानूनन दंडनीय अपराध है और सत्ता में बैठे लोगों से जवाबदेही की मांग करने का समय आ गया है. जस्टिस माथुर ने अंत में कहा कि 'ऐसे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने का यह सही समय है, जो सांप्रदायिक नफरत फैलाता है, जो हमारे कानून के तहत अपराध है।'

बंगाल में चुनाव पर्यवेक्षकों को लेकर भी बवाल, ममता सरकार ने चुनाव आयोग को भेजे अपनी पसंद के नाम!

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. हालांकि इन चुनावों के लिए अभी काफी समय है. इससे पहले ही सियासी सरगर्मी तेज हो चली है. सूबे की सीएम ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रही हैं. तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रही हैं. उन्होंने चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर भी अपना विरोध जताया था. इसके साथ ही सरकार ने चुनाव आयोग (ECI) से 9 IAS अधिकारियों को सेंट्रल ऑब्जर्वर ड्यूटी से छूट देने की मांग की थी।

राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सुचारु प्रशासनिक कामकाज बनाए रखने के लिए इन अधिकारियों को बंगाल में ही रखने की मांग की है. ECI ने 15 IAS अफसरों की सूची जारी की थी, जिस पर राज्य ने आपत्ति जताई और वैकल्पिक नाम भी सुझाए हैं. जिनमें राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना भी शामिल हैं. राज्य सरकार ने चुनाव वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किए जाने से छूट देने का अपील भी की है।

कौन-कौन है सूची में शामिल?

गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना के अलावा, सूची में शामिल अन्य IAS अधिकारियों में अश्विनी कुमार यादव, पीबी सलीम, अवनींद्र सिंह, सौमित्र मोहन, स्मारकी महापात्रा, अर्चना, संजय बंसल, पी मोहन गांधी, शुभंजन दास, पी उलगनाथन,

सौरभ पहाड़ी, रचना भगत, रितेंद्र नारायण बसु रॉय चौधरी और राजनवीर सिंह कपूर शामिल थे. इसके साथ ही राज्य ने IAS अधिकारियों संजय बंसल, पी मोहन गांधी, अवनींद्र सिंह, सौमित्र मोहन, शुभंजन दास, पीबी सलीम, रचना भगत और पी उलगानाथन को भी ड्यूटी से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

सरकार ने क्या की आयोग से मांग?

राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुचारू प्रशासनिक कामकाज सुनिश्चित रखने की बात कही है. सरकार ने कहा कि इसमें आने वाली चुनौतियों देखते हुए इन अधिकारियों को कहीं और चुनावी ड्यूटी पर भेजने के बजाय राज्य में ही तैनात रखने का अनुरोध किया है. शीर्ष चुनाव निकाय ने बुधवार को बंगाल के 15 IAS और 10 IPS अधिकारियों की एक सूची जारी की थी, जिन्हें चुनाव वाले राज्यों में सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया जाना है. राज्य सरकार की तरफ से भले ही नाम दिए गए हों. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि उसने कई बार राज्य सरकार से नाम मांगे थे. इसके बाद भी सरकार ने नाम नहीं दिए थे. इसके बाद सरकार की तरफ से नाम सुझाए गए हैं।

संक्षिप्त ख़बरें

UP- देवीपाटन मंडल के IG अमित पाठक का बड़ा एक्शन, एक इंस्पेक्टर-12 दारोगा को किया सस्पेंड

उत्तर प्रदेश में देवीपाटन मंडल के IG अमित पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है. IG अमित पाठक ने एक इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया. वहीं तीन सब इंस्पेक्टरों के खिलाफ अभी जांच जारी है. बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार और अन्य जांच में ये लोग दोषी पाए गए थे. सस्पेंड होने वालों में गोण्डा के दो, श्रावस्ती के तीन और बहराइच के आठ पुलिसकर्मी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि IG के निर्देशन में बनी SIT इन सभी की जांच कर रही थी. वहीं तीन सब इंस्पेक्टर पर अभी कार्रवाई की तलवार लटक रही है शुक्रवार को IG देवीपाटन मंडल अमित पाठक द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच के एक इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया. साथ ही साथ इन सभी लोगों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं. वहीं तीन सब इंस्पेक्टर के खिलाफ अभी भी जांच चल रही है. इनके खिलाफ भी IG अमित पाठक द्वारा कार्रवाई की जाएगी. शुक्रवार को IG देवीपाटन मंडल अमित पाठक द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच के एक इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया. साथ ही साथ इन सभी लोगों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं. वहीं तीन सब इंस्पेक्टर के खिलाफ अभी भी जांच चल रही है. इनके खिलाफ भी IG अमित पाठक द्वारा कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी ऐसे प्रकरण में, जिसमें वाहन बीमित नहीं होता है या जो चालक होता है, उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है. उसके द्वारा एक्सीडेंट कारित किया जाता है तो ये क्षतिपूर्ति संबंधित व्यक्ति से किए जाने का प्रावधान है. हालांकि कई विवेचनाओं में इनके द्वारा फर्जी तरीके से ऐसे वाहनों को प्रकाश में लाया गया, जिनके द्वारा घटना नहीं की गई थी व ऐसे चालकों को भी प्रकाश में लाया गया. जब इस सबकी अलग-अलग जनपदों में विस्तार से जांच कराई गई तो ऐसे 13 प्रकरण निकलकर आए, जिसमें 16 विवेचकों द्वारा ये अनियमितताएं की गई थीं।

MP- फर्जी नामों पर करोड़ों के लोन, ED ने 5 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के भोपाल जोनल ऑफिस ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शाखा से जुड़े एक लोन घोटाले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मार्क पियस करारी और चार अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की है. यह चार्जशीट बुधवार को भोपाल की विशेष PMLA अदालत में पेश की गई, जिस पर अदालत ने आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर सामने आया था. सीबीआई ने पहले ही इस मामले में मनोज परमार, तत्कालीन बैंक मैनेजर मार्क पियस करारी और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की।

फर्जी नामों पर लिए गए करोड़ों के लोन

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि मनोज परमार ने पंजाब नेशनल बैंक, आष्टा (जिला सीहोर) के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर की मिलीभगत से दो सरकारी योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (CMYUY) के तहत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया. साल 2016 में इन योजनाओं के तहत कुल 18 लोन मंजूर कराए गए, जिनकी कुल राशि करीब 6.20 करोड़ रुपये थी. इनमें से लगभग 6.01 करोड़ रुपये वास्तव में निकाल भी लिए गए.

जांच में सामने आया कि ये लोन फर्जी लोगों के नाम पर, जाली दस्तावेजों और नकली कोटेशन के आधार पर मंजूर किए गए. बैंक के नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया. जहां दूसरी स्तर की मंजूरी जरूरी थी, उसे जानबूझकर छोड़ा गया और ब्रांच मैनेजर की सीमा से ज्यादा रकम के लोन भी पास कर दिए गए।

जमीन पर कोई काम नहीं, सिर्फ कागजों में कारोबार

बाद में जब बैंक अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की तो सच्चाई सामने आ गई. जिन लोगों के नाम पर लोन दिखाए गए थे, उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने न तो कोई आवेदन किया और न ही उन्हें कोई लोन मिला. जिन उद्योगों और व्यवसायों के नाम पर लोन लिया गया था, वे कहीं मौजूद ही नहीं थे. यानी रोजगार देने के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का खुला दुरुपयोग किया गया।

पैसे को घुमाकर बनाई गई काली कमाई

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि लोन की रकम को मनोज परमार और उसके करीबियों की फर्मों के खातों में घुमाया गया. कई खातों के जरिए पैसे को इधर-उधर किया गया, कुछ रकम नकद निकाल ली गई और कुछ से आरोपियों के नाम पर संपत्तियां खरीदी गईं. यह पूरा खेल पैसे के स्रोत को छिपाने और उसे वैध दिखाने के लिए किया गया, जिसे कानून की भाषा में 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' कहा जाता है।

पहले ही जब्त हो चुकी हैं संपत्तियां

इस मामले में ईडी पहले ही मनोज परमार और अन्य आरोपियों की करीब 2.08 करोड़ रुपये की 12 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर चुकी है. ये संपत्तियां मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा इलाके में स्थित हैं।

सव्यसाची इंफ्रा पर चला ईडी का हंटर, रियल एस्टेट घोटाले में 15.4 करोड़ की संपत्ति कुर्क

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ईडी के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने रियल एस्टेट घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है. मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत मेसर्स सव्यसाची इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (SIPL) और उससे जुड़े लोगों की करीब 15.40 करोड़ रुपये की 3 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है. ये संपत्तियां हरियाणा के फर्रुखनगर, गुरुग्राम में हैं. यह कार्रवाई हरियाणा पुलिस और दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज 3 अलग-अलग एफआईआर के आधार पर की गई है. इनमें सव्यसाची इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, उसके डायरेक्टर विजय राजन और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।

बिना लाइसेंस बेचे प्लॉट और फ्लैट

ईडी की जांच में सामने आया है कि सव्यसाची इंफ्रास्ट्रक्चर ने अमाया ग्रीन्स प्रोजेक्ट, अमाया ग्रीन्स एक्सटेंशन और अमाया बाजार नाम से टाउनशिप और एससीओ (SCO) योजनाएं लॉन्च की थीं. इन योजनाओं के तहत कंपनी ने फर्रुखनगर के सेक्टर-3 इलाके में प्लॉट,

फ्लैट और एससीओ देने का लालच देकर निवेशकों से पैसे वसूले. जांच में यह भी खुलासा हुआ कि साल 2019 में कंपनी ने बिना जरूरी सरकारी लाइसेंस, मंजूरी और जमीन के मालिकाना हक के ही बुकिंग शुरू कर दी थी. यानी कागजों में प्रोजेक्ट थे, लेकिन जमीन और मंजूरी हकीकत में मौजूद नहीं थी।

न वादा पूरा हुआ, न पैसा वापस मिला

कंपनी ने निवेशकों से वादा किया था कि एक साल के भीतर प्लॉट या एससीओ का कब्जा दे दिया जाएगा. तब तक निवेश की रकम पर तय रिटर्न भी मिलेगा. मगर, ना तो किसी को प्लॉट मिला और ना ही कोई रिटर्न. इतना ही नहीं जिन लोगों से पहले ही बुकिंग ली जा चुकी थी, उन्हीं प्लॉट्स के कागज तीसरे लोगों के नाम पर भी कर दिए गए. ईडी के मुताबिक, इस तरह करीब 100 से ज्यादा निवेशकों को ठगा गया. निवेशकों से ली गई रकम न तो लौटाई गई और न ही किसी तरह की निर्माण गतिविधि मौके पर नजर आई।

पैसा इधर-उधर घुमाकर खरीदी जमीन

जांच में यह भी सामने आया है कि कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटरों ने निवेशकों से जुटाए गए पैसों को अपने करीबी और बेनामी लोगों के नाम पर जमीन खरीदने में लगाया. अब तक की जांच के अनुसार इस मामले में करीब 18 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) की गई।

आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

पुलिस ने तीनों एफआईआर में सव्यसाची इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर विजय राजन, हर्ष खन्ना और अन्य सहयोगियों- दीपक गुप्ता, मनीष तुषीर, मोहन लाल, मनोज दुबे, आशा कौशिक, राघव कौशिक, संजीव शर्मा और सत्यजीत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।

सोनम वांगचुक ने कोर्ट में कहा- मैं सरकार की आलोचना कर सकता हूं, सरकारी कार्रवाई का विरोध एंटी-नेशनल नहीं

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो इस समय जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं, ने शीर्ष अदालत में दलील दी है कि लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी और स्वदेशी संस्कृति की रक्षा के लिए उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने में सरकार की देरी या निष्क्रियता की शांतिपूर्ण आलोचना को राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं माना जा सकता. रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वांगचुक सितंबर 2025 से जेल में हैं. उन्हें उस समय हिरासत में लिया गया था जब लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए थे. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश होते हुए वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार ही राष्ट्र नहीं होती. सिब्बल ने अदालत में दलील दी, 'मैं सरकार की आलोचना कर सकता हूं सरकार की कार्रवाई या निष्क्रियता के खिलाफ विरोध को न तो राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है और न ही राज्य विरोधी. मैं शांतिपूर्ण मार्चों और प्रदर्शनों के माध्यम से असहमति व्यक्त कर सकता हूं' वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस आरोप से इनकार किया कि उन्होंने सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 'अरब स्प्रिंग' जैसी किसी क्रांति का आह्वान किया था. ज्ञात हो कि अरब स्प्रिंग पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में वर्ष 2010 से 2018 के बीच हुए सरकार-विरोधी हिंसक आंदोलनों की श्रृंखला को कहा जाता है. उन्होंने लद्दाख की स्वच्छ और प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए वांगचुक द्वारा वर्षों से किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान दिलाया. सिब्बल ने कहा कि लद्दाख में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है, जो क्षेत्र की विशिष्ट और संवेदनशील पारिस्थितिकी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. सिब्बल ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने नजरबंदी आदेश जारी करने वाली प्राधिकरण को गुमराह करने के लिए चुनिंदा वीडियो भेजे हैं. उन्होंने इस आरोप को भी खारिज किया कि वांगचुक ने किसी साक्षात्कार में यह कहा था कि बाहरी आक्रमण की स्थिति में लद्दाख के लोग सेना की मदद नहीं करेंगे. सिब्बल ने कहा, 'यह गलत है, यही इस मामले की समस्या है. अधिकारियों ने प्राधिकरण को गुमराह किया है. मेरे पास उसी वीडियो का लिंक है जिसमें वह सरकार और प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, वीडियो में शांतिपूर्ण विरोध का स्पष्ट उल्लेख है.' वरिष्ठ अधिवक्ता ने वांगचुक पर हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि हैकर्स और ट्रोल्स ने गलत तरीके से इसे प्रचारित किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, सिब्बल ने कहा, 'बिना एडिट किए वीडियो पूरी तस्वीर सामने लाता है. उनका आशय यह था कि कश्मीर से लद्दाख को अलग करने के बाद केंद्र सरकार संविधान की छठी अनुसूची के तहत दी जाने वाली सुरक्षा का अपना वादा निभाने में असफल रही. उन्होंने एक रूपक (allegorical) के तौर पर कहा कि जैसे भगवान राम ने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाया और फिर छोड़ दिया, उसी तरह केंद्र सरकार ने लद्दाख के साथ किया.' उन्होंने आगे कहा, 'यह केवल भगवान राम से जुड़ा एक अलंकारिक उदाहरण था. अगर ऐसे बयानों के आधार पर किसी को हिरासत में लिया जाएगा, तो फिर बोलना ही बंद कर देना चाहिए. उनकी पत्नी स्वयं एक हिंदू हैं।'

सिब्बल ने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी नागरिक को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है.

उन्होंने कहा, 'वह कहते हैं कि वे किसी भी तरह की हिंसा नहीं होने देंगे. छठी अनुसूची एक राजनीतिक दल द्वारा किया गया वादा है, जो 2020 में दिया गया था. अगर 2025 में कोई चुनाव से पहले उस वादे को पूरा करने की मांग करता है, तो इसमें गलत क्या है? सरकार-विरोधी भावनाएं राज्य की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करतीं. मैं सरकार की आलोचना कर सकता हूं - हम यह हर समय करते हैं. यही लोकतंत्र है. और लोकतंत्र का हिस्सा शांतिपूर्ण विरोध और पदयात्राएं हैं. क्या शांति भंग करने को लेकर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोई कार्रवाई हुई? नहीं.' सिब्बल ने वांगचुक की पेट से जुड़ी बीमारी को लेकर किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच कराने का अनुरोध भी किया. उन्होंने कहा कि यह बीमारी दूषित पानी के कारण हुई है. वांगचुक को राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है, जो उनके गृह नगर लेह से लगभग 1,400 किलोमीटर दूर है. मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी।

'मंत्री और सांसद के सामने झूठ बोलते हो', उन्नाव में अफसरों पर क्यों भड़के BJP विधायक?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के भगवंत नगर से विधायक आशुतोष शुक्ला अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. एक बार फिर उन्होंने अपने क्षेत्र में काम न होने पर अफसरों को फटकार लगाई है. उन्होंने अफसरों को डांटते हुए कहा कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मैं खड़ा हो जाऊंगा. उन्होंने अधिकारी और ठेकेदारों पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।

दरअसल यह पूरा मामला भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला के कार्यक्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है. विधायक का आरोप है कि उनके क्षेत्र में काफी धीमा चल रहा है. विधायक शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का मुआयना कर रहे थे. इसी बीच इंटरलॉकिंग सड़क के निरीक्षण के दौरान जगह-जगह टूटी हुई ईंटें, मानक से कम सामग्री और अधूरा कार्य पाया गया, जिस पर विधायक ने ठेकेदारों और अधिकारियों से जवाब तलब किया।

लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं

विधायक आशुतोष शुक्ला ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कहा कि जनता के पैसे से हो रहे विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मैं खड़ा हो जाऊंगा और नंगा नाच करके दिखाऊंगा. विधायक ने कहा हम वो नहीं है जो चाय कॉफी पीकर चले जाएं. धरातल पर हमें काम दिखाओ और धरातल पर हमें काम दिखना चाहिए. विधायक ने साफ कहा कि जनता ने उन्हें काम कराने के लिए चुना है और वे जनता के विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।

सांसद और मंत्री के सामने झूठ बोलते हो

विधायक ने आगे कहा कि जब सांसद और मंत्री आते है तब तुम सब लोग मिलकर उनके सामने झूठ बोलते हो. उन्हें झूठी रिपोर्ट पेश करते हो. विधायक ने अब ये सब नहीं चलेगा. जमीन पर काम दिखना चाहिए था. उन्होंने कहा कि ढाई साल पहले जो काम होना था वह आजतक नहीं हुआ. इसका क्या मतलब है. उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि इंटरलॉकिंग का कार्य दोबारा मानक के अनुसार कराया जाए और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इस मामले की चार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

स्थानीय ग्रामीणों को विधायक ने दिलाया भरोसा

इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने भी विधायक को अपनी समस्याएं बताई और घटिया निर्माण कार्य की शिकायत की. विधायक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य कराए जाएंगे. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि तय समयसीमा में गुणवत्ता के साथ काम पूरा नहीं हुआ, तो वे चुप नहीं बैठेंगे. उन्होंने काम करा रहे संबंधित अधिकारी और ठेकेदारों को आड़े हाथों ले लिया. उनके इस बयान से मौके पर मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

शब्दों से युद्ध तक: 'अगला हमला' और बदलती वैश्विक रणनीति

[भयानक हमला: चेतावनी या आत्म-घोषित युद्ध?]

[ईरान सिर्फ बहाना? ट्रंप की धमकी के पीछे छिपा बड़ा खेल]

वॉशिंगटन की जमी हुई राजनीतिक हवा में जब यह वाक्य उछला– 'अगला हमला बहुत भयानक होगा '–तो वह महज़ चेतावनी नहीं रहा, बल्कि भविष्य के अंधेरे की ओर फेंका गया एक साया बन गया। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द कभी सामान्य नहीं होते; वे संकेत होते हैं, इशारे होते हैं, और कई बार इतिहास की धुरी मोड़ देने वाली घोषणाएँ भी, जैसे जनवरी 2026 में ट्रूथ सोशल पर उनकी पोस्ट में 'द नेक्स्ट अटैक विल बी फ़ार वर्स!' का उद्घोष। 2026 की दहलीज़ पर खड़ी दुनिया, जो महामारी की थकान, जलवायु आपदाओं और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही है, इस वाक्य को सुनकर सिहर उठी। यह बयान युद्ध की औपचारिक घोषणा भले न हो, लेकिन उसकी गंध साफ महसूस होती है। यह डर भी पैदा करता है, भ्रम भी रचता है और पूरी मानवता को इस बेचैनी में डाल देता है कि अगली तबाही किस दिशा से आएगी। स्वाभाविक है कि इस धमकी की सुई सबसे पहले ईरान पर जाकर टिकती है। अमेरिका और ईरान के संबंध दशकों से अविश्वास, प्रतिबंधों और टकराव की आग में जलते रहे हैं। परमाणु महत्वाकांक्षाएँ, इज़रायल के साथ छद्म युद्ध और फारस की खाड़ी में बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ पहले ही हालात को बारूद बना चुकी हैं। ऐसे माहौल में ट्रंप का यह बयान, और उसके साथ क्षेत्र में बढ़ती अमेरिकी सैन्य मौजूदगी, किसी संकेत से कम नहीं। यह साफ झलक देता है कि ईरान को चेताया जा रहा है कि अगर परमाणु डील नहीं हुई, तो अगला हमला पिछले (जून 2025 के स्ट्राइक्स) से 'फ़ार वर्स' होगा।

ईरान की भीतरी हालत इस धमकी को और भी भयावह बना देती है। आर्थिक बदहाली, मुद्रा का गिरता मूल्य, बेरोजगारी और युवाओं के बीच पनपता असंतोष–इन सबके बीच सत्ता का कठोर रवैया समाज की जड़ों को कमजोर कर रहा है। ट्रंप की भाषा मानो यह संदेश देती है कि अमेरिका इन दरारों को रणनीतिक अवसर की तरह देख रहा है। लेकिन इतिहास बार-बार यही सवाल उठाता है–क्या बाहरी सैन्य दबाव किसी देश को सुधार सकता है, या वह केवल अराजकता को और गहरा करता है? अनुभव बताता है कि ऐसे हमलों का सबसे भारी बोझ हमेशा सत्ता पर नहीं, बल्कि आम नागरिकों के कंधों पर ही टूटता है। फिर भी ट्रंप की इस धमकी को केवल ईरान तक सीमित मानना एक गंभीर भूल होगी। उनकी राजनीति की सबसे पहचानने योग्य विशेषता यही है कि वह जानबूझकर अस्पष्ट रखी जाती है। रूस, जो यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिम से सीधे टकराव की स्थिति में है, आज भी अमेरिकी रणनीतिक सोच के केंद्र में बना हुआ है। चीन, जो ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अपनी शक्ति का खुला प्रदर्शन कर रहा है, वॉशिंगटन के लिए एक दीर्घकालिक और निर्णायक चुनौती बन चुका है। वहीं उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम किसी भी क्षण हालात को विस्फोटक बना सकता है। हालांकि ट्रंप का यह स्पेसिफिक बयान ईरान पर केंद्रित है, लेकिन उनकी समग्र नीति (जैसे एनडीएस 2026) में चीन मुख्य थ्रेट है, और रूस/उत्तर कोरिया भी रडार पर बने हुए हैं। ऐसे परिदृश्य में 'अगला हमला' एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक खुला संदेश बन जाता है–जो भी अमेरिकी लाल रेखाएं पार करेगा, उसके लिए परिणाम सुरक्षित नहीं होंगे। आज के समय में युद्ध की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। अब लड़ाइयां केवल रणभूमि या सीमाओं तक सीमित नहीं रहीं। आर्थिक प्रतिबंध, साइबर हमले, सूचना युद्ध और कूटनीतिक दबाव आधुनिक युद्ध के सबसे प्रभावी हथियार बन चुके हैं। ट्रंप का यह बयान उसी मानसिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा प्रतीत होता है। एक ही वाक्य वैश्विक बाजारों में भूचाल ला सकता है, तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकता है और निवेशकों के भरोसे को डगमगा सकता है। आज शब्द मिसाइलों जितने ही घातक हो चुके हैं, और ट्रंप इस ताकत का इस्तेमाल करना भली-भांति जानते हैं। ट्रंप की इस रणनीति को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 'ब्रिंकमैनशिप' कहा जाता है–यानी दुनिया को जानबूझकर कगार तक ले जाना, ताकि सामने वाला पहले पीछे हट जाए। यह रणनीति दिखने में प्रभावी लग सकती है, लेकिन इसमें जोखिम असाधारण रूप से ऊंचा होता है। कगार पर खड़े होकर संतुलन बिगड़ने में सिर्फ एक पल लगता है। यदि किसी संकेत को गलत समझ लिया गया, या किसी पक्ष ने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दे दी, तो सीमित टकराव भी पूर्ण युद्ध का रूप ले सकता है। खासकर तब, जब सामने खड़े देश भी तकनीकी और सैन्य रूप से सक्षम हों और पीछे हटने को तैयार न हों। ट्रंप स्वयं को शांति का सौदागर कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी भाषा में शांति की नरमी कम और शक्ति का कठोर प्रदर्शन अधिक झलकता है। यही विरोधाभास उनकी राजनीति की स्थायी पहचान बन चुका है। उनका विश्वास है कि भय पैदा करके स्थिरता कायम की जा सकती है, जबकि इतिहास बार-बार साबित करता है कि डर अक्सर अस्थायी शांति और स्थायी संघर्ष को जन्म देता है। मध्य पूर्व पहले ही युद्ध, अस्थिरता और विभाजन की मार झेल रहा है। यदि वहां एक और बड़ा सैन्य टकराव भड़कता है, तो उसके झटके सीमाओं में नहीं रुकेंगे, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामूहिक सुरक्षा तंत्र को गहराई तक हिला देंगे। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा नुकसान उस आम इंसान का होता है, जिसका किसी रणनीति, सत्ता या भू-राजनीतिक खेल से कोई लेना-देना नहीं होता। युद्ध की धमकियां नेताओं के भाषणों में जन्म लेती हैं, लेकिन उनकी कीमत नागरिक चुकाते हैं–घर उजड़ते हैं, रोज़गार छिन जाते हैं और डर रोज़मर्रा की जिंदगी का स्थायी साथी बन जाता है। ट्रंप की यह धमकी सुरक्षा का भरोसा नहीं देती, बल्कि अनिश्चितता और आशंका को और गहरा करती है। शायद यही कारण है कि इस बयान के बाद दुनिया के कई हिस्सों में बेचैनी और असहजता साफ महसूस की जा रही है। ट्रंप का वर्तमान निशाना मुख्य रूप से ईरान है, जहाँ 'मैसिव आर्माडा' भेजे जाने की तैयारी दिखाई दे रही है और परमाणु डील की सख़्त माँग दोहराई जा रही है। यह बयान एक असहज करने वाली सच्चाई को उजागर करता है–2026 की दुनिया तकनीक, सूचना और ज्ञान में चाहे जितनी भी उन्नत क्यों न हो गई हो, उसकी मानसिकता अब भी युद्ध की पुरानी और भयावह परछाइयों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकी है। यदि सचमुच 'अगला हमला' हुआ, तो वह केवल भयानक ही नहीं होगा, बल्कि ऐसा गहरा घाव छोड़ेगा जिसे भरने में दशकों नहीं, शायद पीढ़ियाँ लग जाएँ। अब यह वैश्विक समुदाय पर निर्भर करता है कि वह भय और टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ता है, या संवाद, संयम और विवेक का साहसिक विकल्प चुनता है।

प्रो. आरके जैन

विकासशील देशों में संसाधनों की कमी, पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन

वर्तमान में पृथ्वी तथा प्राकृतिक संसाधनों के विनाशकारी जलवायु परिवर्तन की गति तथा उसके प्रभाव में गति की तीव्रता तेजी से महसूस की जाती रही है। इसका और कोई कारण ना होकर मानव की अवांछित गतिविधियां ही हैं। जिनमें मूलतः वन का विनिष्टिकरण, जीवाश्म ईंधन का ताबड़तोड़ प्रयोग, नई कृषि नीति तथा पद्धति की तीव्रता से होते हुए उद्योगों की संरचना और कंक्रीट के जंगलों यानी शहरों का विस्तारीकरण बड़े कारण हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान से उत्पादित औद्योगिकरण के विकास के साथ मनुष्य ने वायुमंडल के प्रक्रियागत प्रभाव में बदलाव लाना शुरू किया है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी में भूमंडलीय ऊष्मा का विस्तार ओजोन परत का क्षरण, असामयिक बाढ़,अकाल का आना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि से हरित गृह प्रभाव की घटना प्रभावित हुई है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी की एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी का निचला स्तर मंडल गर्म बना रहता है. तथा जीवन के अनुरूप वायुमंडल में वातावरण जीवन उपयोगी तथा जीवन के अनुकूल बना रहता है। किंतु ग्रीन हाउस इफेक्ट में बदलाव आने के साथ ही मनुष्य के सामने जलवायु परिवर्तन की बड़ी समस्या सामने आई है। इस तरह के परिवर्तन से ही पृथ्वी की परत को हमें बचाना होगा जिससे हम अति उष्णता, गर्म जलवायु और कम उत्पादन की विभीषिका से मानव को बचा सकते हैं।

(विश्व में विकासशील देश दोहरी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, पहली भुखमरी यानी कि गरीबी दूसरी जलवायु में तीव्र परिवर्तन और यह दोनों एक दूसरे से गहरे संबंधित हैं। विकासशील तथा गरीब राष्ट्र एक और गरीबी तथा भुखमरी से लड़ाई लड़ रहे हैं एवं गरीबी से छुटकारा पाकर गरिमामय जीवन जीना चाहते हैं ।इसके लिए वे अपने प्राकृतिक, वैज्ञानिक संसाधनों का दोहन करके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं जिससे इनके सम्मुख कई चुनौतियां उत्पन्न हो जाती है) इनके पास पर्याप्त रूप से आर्थिक वित्तीय पूंजी की कमी साथ ही उन्नत तकनीक का अभाव भी है। ऐसे में यह विकासशील राष्ट्र के विकास हेतु परंपरागत विकास साधनों पर आश्रित हो जाते हैं, जैसे विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करना, वाहनों में प्रयुक्त ईंधन की गुणवत्ता का निम्न होना, कारखानों की पुरानी मशीनों द्वारा कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि तत्वों की बड़ी मात्रा में वायु को उत्सर्जित करना आदि आते हैं। इन सब के कारण ग्रीन हाउस गैसें निर्मित होने से ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन घटनाओं को तीव्रता प्राप्त होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापक्रम जैसे कारकों में बहुत तेजी से परिवर्तन होता आया है। इसके पश्चात वर्षा की अनिश्चितता तथा अनियमितता में वृद्धि हुई है साथ ही बाढ़ सूखा अकाल सुनामी हिमस्खलन भूस्खलन जैसी प्राकृत आपदाओं का कई देश हर वर्ष सामना करते आ रहे हैं। उनके सम्मुख बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न होती आई है, और यही प्राकृतिक आपदाएं उन देशों को फिर से गरीबी के दलदल में ढकेल देती है जहां भुखमरी का बोलबाला होता है। विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जिनमें जिंबाब्वे, सीरिया,लीबिया, सोमालिया तथा अधिकांश अफ्रीकी देश, दक्षिण एशियाई लैटिन अमेरिकी देशों में भोजन,रोटी के लिए लंबी-लंबी लाइन लगती देखी गई है। दूसरी तरफ विकसित और अमीर देशों में भी लाइन लगती है, लेकिन वहां पर विडंबना यह है कि यह लाइन रोटी के लिए नहीं बल्कि आईफोन, स्मार्टफोनऔर गैजट्स के लिए लगाई जाती है।

अनेक गरीब देशों में सबसे बड़ा संकट विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लेकर सामने आया है। जहां यह देश विकास की इच्छा तो रखते हैं पर दूसरी और विकसित देश गरीब देशों को पर्यावरण संरक्षण की सीख दे कर इनके संसाधनों पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं। जिससे इनके अस्तित्व तथा संप्रभुता पर गहरी चोट लगती है। यह एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण जैसी बातें गरीबी के सामने एक चुनौती के रूप में दिखाई देती है। यदि ये देश भुखमरी, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी जैसे समस्याएं को सुलझाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलन बिठाना कठिन हो जाता है। आज विकसित देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य अमीर यूरोपीय देश पर्यावरण संतुलन की बात तो करते हैं पर जहां तकनीकी मदद या संरक्षण की बात को तो यह अपना हाथ पीछे खींचने में भी नहीं चुकते हैं। गरीब तथा विकासशील देश जब भी विकास को प्राथमिकता देने का प्रयास करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण को क्षति होना लाजमी होता है। इसके अलावा इन्हें वैश्विक महाशक्तियों के दबाव भी झेलने पड़ते हैं। गरीब देशों के उत्पादों को खरीदने में बड़े बाजार या यूं कहें कि विकसित राष्ट्र गुणवत्ता की कमी,तकनीकी कमी कहकर तिरस्कृत तथा वापस करने से नहीं चूकते हैं। इस मामले में विकसित राष्ट्र का विकासशील,गरीब राष्ट्र के बीच एक गहरी खाई बन चुकी है और संयुक्त राष्ट्र संघ मूकदर्शक बना इस मामले में हाथ में हाथ धरे बैठा रहता है। बड़ी जनसंख्या वाले देश जैसे भारत इंडोनेशिया एवं एशिया के अन्य देश विकसित राष्ट्रों के लिए एक बड़ा बाजार जरूर है, पर वहां पर भूखमरी और जलवायु परिवर्तन के मामले में ये सभी बड़े तथा विकसित राष्ट्र खामोश रहते हैं। विकासशील तथा निर्धन देशों में गरीबी, भुखमरी तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण गृह संघर्ष, जातीय संघर्ष,मानव अधिकार उल्लंघन, शरणार्थी समस्या, उग्रवाद, आतंकवाद आदि गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और और इनकी स्थितरता में बड़ी कमी आई है। पिछले विगत कुछ समय एक घटनाक्रमों से शरणार्थी संकट ग्रह संघर्ष के विस्थापन अकाल बाढ़ तथा आतंकवाद मैं चिंताजनक वृद्धि हुई है, और यह सब पूरे विश्व के लिए चुनौती बन गया है। यह अलग बात है कि विकासशील राष्ट्रों की कमजोर क्षमता के कारण यह चुनौती उन देशों को बड़ी विकराल लगती है क्योंकि इससे पूंजीगत संसाधनों में बड़ी क्षति होती है जिस का संतुलन करना वहां की सरकारों पर बहुत भारी पड़ जाता है। गरीबी रेखा के नीचे लोग ज्यादा जीवन यापन करने लगते हैं। वैश्विक स्थिति का अध्ययन करें तो गरीबी भूखमरी जलवायु परिवर्तन से लड़ना किसी एक देश के लिए संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह वैश्विक समस्या है। इसे सम्मिलित रूप से ही प्रयास कर समाप्त किया जा सकता है। यह तो तय है कि विकासशील राष्ट्रों को उन्नत बनाने तथा विकसित करने में बड़े तथा सक्षम राष्ट्रों को इन छोटे तथा गरीब देशों की तकनीकी विज्ञान और पूंजीगत सहायता प्रदान करनी चाहिए। अपने महंगी खर्चीली परमाणु तथा अणु बम तथा मिसाइल बनाने की योजनाओं को एक तरफ रख विकासशील राष्ट्रों की खुलकर मदद करनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में ही वैश्विक भुखमरी गरीबी एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटा जा सकता है। भारतीय संदर्भ में यह जरूर कहा जा सकता है कि विगत 10 वर्षों में जलवायु परिवर्तन तथा गरीबी उन्मूलन पर बहुत ज्यादा प्रयास कर नई नई योजनाएं बनाई गई हैं। जैसे राष्ट्रीय हरित मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन मिशन पर बहुत सारी योजनाये बनाकर कार्य किया गया है। भारत देश अपनी योजनाओं में छोटे विकासशील राष्ट्रों को भी शामिल किया है और उनकी खुलकर मदद कर रहा है, यह विकसित राष्ट्रों के लिए एक उदाहरण भी है कि उन्हें छोटे तथा गरीब राष्ट्रों को खुलकर मदद करनी चाहिए।

संजीव ठाकुर

सिख युवकों का फौज के प्रति कम होता रूझान

एक समय था जब भारतीय फौज में सिखों की गिनती सबसे अधिक हुआ करती थी। सिख युवक सिख रेजीमेंट के अलावा सिख इनफैंटरी, पंजाब रेजीमेंट, आर्टलरी, गौरखा, आरमर्ड सहित अन्य रेजीमेंट में भी बड़ी गिनती में भर्ती हुआ करते थे। सिख रेजीमेंट सबसे अधिक मैडल जीतने वाली रेजीमेंट थी और एक समय में तो कामनवैल्थ में सबसे ऊपर इसका नाम आता था। पंजाब के तकरीबन हर घर से एक ना एक बच्चा फौज में भेजा जाता था और कई घर तो ऐसे भी हैं जिनमें कई पीढ़ियां फौज में गई, पर आज सिख युवकों की फौज के प्रति रुचि कम होती देख देश की सेना के द्वारा सिखों को सेना में भर्ती होकर सिख रेजीमेंट से जुड़ने की अपील की गई है जो दर्शाता है कि आज भी समूचे देश को सिखों की देशभक्ति पर गर्व है और वह भलिभान्ति जानते हैं कि सिख सैनिक मुश्किल आने पर कभी पीछे नहीं हटता या तो सामने वाले को मिटा देता है या फिर खुद देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि 19वीं सदी में खालसा आर्मी द्वारा अफगानिस्तान विजय करने के बहादुरी वाले किस्सों से प्रभावित होकर ब्रिटिश हकूमत ने सिखों को भारतीय फौज में शामिल करते हुए उन्हें सिख पायोनियर्स का खिताब दिया गया। 1846 में सिख रेजीमेंट की स्थापना हुई। 1932 में जब स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष जोरों पर था, स्वतंत्रता संग्राम में भी सिखों द्वारा आगे आकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चे लगाए जा रहे थे, ऐसे में मार्शल कौम से गौरों को भय सताने लगा और उन्होंने सिख बटालियनों को भंग कर दिया। 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के समय उन्हें अधिक फौज की आवश्यकता हुई तो फिर से बड़ी गिनती में सिखों को फौज में शामिल किया गया और सिख रेजीमेंट के अतिरिक्त सिख लाईट इनफैंटरी रेजीमेंट की भी स्थापना की गई जो कि आज भी कायम है और 20 रैगुलर बटालियन, 3 टेरिटोरियल आर्मी इसमें काम कर रही है। आजादी से पूर्व 245 और आजादी के उपरांत 82 मैडल सिख रेजीमेंट के बहादुर जवानों ने जीते जिसमें 21 इंडीयन आर्डर आफ मैरिट, 14 विक्टोरिया, 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक, 8 महावीर, 24 कीर्ति, 64 वीर, 55 शौर्य चक्र के अलावा 375 सेना मैडल प्राप्त किये हैं। पहला अग्निवीर पदक हासिल करने वाला सैनिक भी 7 सिख लाईट एनफेंटरी से आया। सिख सैनिकों की फौज में कम होती गिनती के पीछे कुछ लोग सिख युवकों का रुझान विदेशों की ओर बढ़ने का तर्क देते हैं मगर सरदार हिम्मत सिंह जिनका पारिवारिक सम्बन्ध फौज से रहा है और इनके परिवार के कई सदस्य आज भी भारतीय फौज का हिस्सा हैं। हिम्मत सिंह का कहना है कि सिखों का विदेशों में पलायन का सिलसिला तो बीसवीं सदी के शुरू से ही हो गया था, यह कोई नया नहीं है। बावजूद इसके इतने सालों से सेना में भी बड़ी गिनती में सिख भर्ती हुए। असल में जबसे राज्य की जनसंख्या के हिसाब से फौज में भर्ती होने लगी तब से पंजाब से गिनती कम होने लगी। दूसरा अग्निवीर स्कीम भी इसका एक कारण है जिसके लिए सरकार को थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। इस स्कीम के आने से सिपाही और अग्निवीर में फर्क दिखने लगा जबकि दोनों ही जवान सेना में रहकर देश के लिए मर-मिटने को तैयार रहते हैं। फिर अग्निवीर की 4 साल बाद रिटार्यरमेंट होने के बाद कोई पैंशन या अन्य लाभ भी नहीं हैं। इसलिए सिर्फ अपील से कुछ नहीं होगा, इसकी गहराई पर विचार करने की आवश्कता है। विदेशों से संचालित पंजाबी अंडरवर्ल्ड पंजाब जिसे गुरुओं, पीरों की धरती माना जाता है और पंजाब के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विदेशों में जाकर पंजाब ही नहीं बल्कि समूचे देश को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यह लोग विदेशों में बैठकर पंजाबी अंडरवर्ल्ड चला रहे हैं जिसके चलते आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि पंजाब में गैंगस्टर कल्चर दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है जो कि बेहद चिन्ता का विषय है। इसके पीछे क्या कारण रहे, कौन इसके लिए जिम्मेवार है यह मायने नहीं रखता अब सोचना यह होगा कि इसे किस प्रकार रोका जाए। बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि सरहद पार की लड़ाई लड़कर ही इस पर काबू पाया जा सकता है क्योंकि निश्चित तौर पर इन्हें फन्डिंग, हथियार आदि की आर्पूति पड़ौसी मुल्क के द्वारा ही की जाती है जिसकी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी भी प्रकार भारत में दहशत का माहौल बनाया जाए।

संपादकीय

राष्ट्र की आत्मा शहीदों में बसती है और जब तक हम उन्हें स्मरण करते रहेंगे, तब तक भारत की चेतना जीवित रहेगी

30 जनवरी भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर में केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जो हमें हमारे राष्ट्र की आत्मा, उसके संघर्ष, उसके नैतिक मूल्यों और उन अनगिनत बलिदानों की याद दिलाता है जिनकी नींव पर आज़ाद भारत खड़ा है। यह दिन शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से जुड़ा है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। यह क्षण केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं था, बल्कि मानवता, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली चेतना को झकझोर देने वाला क्षण था। इसी कारण 30 जनवरी को भारत अपने सभी शहीदों को स्मरण करता है और उनके सर्वोच्च त्याग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। महात्मा गांधी का जीवन और बलिदान भारत की स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा रहा है। उन्होंने सत्य और अहिंसा को केवल राजनीतिक हथियार नहीं, बल्कि जीवन का मूल दर्शन बनाया। उनका विश्वास था कि हिंसा से प्राप्त विजय टिकाऊ नहीं होती, जबकि नैतिक बल से प्राप्त स्वतंत्रता समाज को स्थायी रूप से बदल देती है। जब 30 जनवरी 1948 को उन्हें हमसे छीन लिया गया, तब पूरा देश शोक में डूब गया। उस दिन भारत ने न केवल अपने राष्ट्रपिता को खोया, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक को भी खो दिया जिसने दुनिया को यह सिखाया कि बिना हथियार उठाए भी साम्राज्य झुकाए जा सकते हैं। शहीद दिवस इसी ऐतिहासिक पीड़ा और प्रेरणा का प्रतीक है।

शहीद दिवस का उद्देश्य केवल अतीत को याद करना नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य को दिशा देना भी है। इस दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सुबह 11 बजे पूरे देश में दो मिनट का मौन रखा जाता है। यह मौन केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का क्षण है, जब हर नागरिक अपने भीतर यह प्रश्न करता है कि क्या हम उन आदर्शों पर चल रहे हैं जिनके लिए हमारे शहीदों ने अपना जीवन न्योछावर किया। यह मौन हमें शोर से भरी दुनिया में ठहरकर सोचने का अवसर देता है। भारत का इतिहास शहीदों की गाथाओं से भरा पड़ा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सीमाओं की रक्षा तक, हर युग में भारत की मिट्टी ने अपने सपूतों का लहू देखा है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों ने विदेशी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने प्राणों की आहुति दी। सैनिकों ने सीमाओं पर खड़े होकर अपने परिवार, अपने सुख और अपने भविष्य को त्याग कर देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। इन सभी शहीदों का जीवन हमें यह सिखाता है कि राष्ट्र केवल एक भूगोल नहीं है, बल्कि एक साझा चेतना है, जिसकी रक्षा के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग आवश्यक होता है।

शहीदों की प्रशंसा केवल उनके साहस और वीरता के लिए नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्यबोध के लिए भी की जानी चाहिए। शहीद वे लोग थे जिन्होंने यह समझा कि देश के प्रति जवाबदेही केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में निभाई जाती है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। किसी ने फांसी का फंदा हंसते-हंसते स्वीकार किया, तो किसी ने बर्फीली चोटियों पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था और व्यक्तिगत जीवन गौण। यही भावना उन्हें साधारण नागरिकों से असाधारण बनाती है। शहीद दिवस उन आत्माओं की स्मृति है जिन्होंने इसी मिट्टी के लिए सर्वोच्च त्याग किया और अंततः इसी मिट्टी में समाहित हो गए। उनकी राख, उनका लहू और उनकी स्मृतियां इस देश की धमनियों में बहती हैं। जब हम आज़ादी की हवा में सांस लेते हैं, तो उसमें उनके बलिदान की सुगंध भी घुली होती है। जब हम लोकतंत्र के अधिकारों की बात करते हैं, तो उसके पीछे उनकी कुर्बानियों की मजबूत दीवार खड़ी होती है। इसलिए शहीद दिवस केवल श्रद्धांजलि का दिन नहीं, बल्कि कृतज्ञता का दिन है।

महात्मा गांधी की शहादत हमें यह भी सिखाती है कि मतभेदों का समाधान हिंसा नहीं हो सकता। उन्होंने अपने जीवन में बार-बार कहा कि अहिंसा कायरों का नहीं, बल्कि साहसी लोगों का हथियार है। शहीद दिवस पर गांधीजी को याद करना हमें उनके इस संदेश की ओर लौटने का अवसर देता है। आज जब समाज में असहिष्णुता, वैमनस्य और हिंसा के स्वर तेज़ होते जा रहे हैं, तब गांधी का दर्शन और भी प्रासंगिक हो जाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने में है। शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि केवल पुष्पांजलि अर्पित करने या मौन रखने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह श्रद्धांजलि तब पूर्ण होती है, जब हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। एक जिम्मेदार नागरिक बनना, कानून का सम्मान करना, समाज में सद्भाव बनाए रखना और देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना ही शहीदों के बलिदान का वास्तविक सम्मान है। जब एक छात्र ईमानदारी से पढ़ाई करता है, जब एक किसान मेहनत से अन्न उगाता है, जब एक सैनिक सीमा पर सतर्क रहता है और जब एक नागरिक संविधान का सम्मान करता है, तब शहीदों का सपना साकार होता है।

शहीद दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वतंत्रता स्थायी नहीं होती, उसे निरंतर सजगता से संभालना पड़ता है। जिन मूल्यों के लिए शहीदों ने बलिदान दिया, यदि हम उन्हें भूल जाएं, तो उनकी कुर्बानी अधूरी रह जाती है। इसलिए यह दिन आत्ममंथन का दिन है। यह हमें पूछने पर मजबूर करता है कि क्या हम सत्य, अहिंसा, समानता और न्याय जैसे मूल्यों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। क्या हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने की थी। अंततः 30 जनवरी का दिन हमें झुककर नमन करना सिखाता है। यह दिन अहंकार को त्याग कर कृतज्ञता को अपनाने का संदेश देता है। जब पूरा देश दो मिनट के मौन में एक साथ खड़ा होता है, तब वह मौन शब्दों से अधिक बोलता है। वह मौन कहता है कि हम अपने शहीदों को भूले नहीं हैं। वह मौन यह वादा करता है कि हम उनके सपनों के भारत को साकार करने का प्रयास करेंगे। शहीद दिवस हमें यह याद दिलाता है कि राष्ट्र की आत्मा शहीदों में बसती है और जब तक हम उन्हें स्मरण करते रहेंगे, तब तक भारत की चेतना जीवित रहेगी।

कांतिलाल मांडोत

बेहतर हो आत्मचिंतन करें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

सदाचार और धर्म का आधार मर्यादा है। आचरण व्यवहार और नैतिकता की निर्धारित सीमाएं मनुष्य को अनुशासित सभ्य और सुसंस्कृत बनाती है मर्यादा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन रखतीं है। धर्म की मर्यादा का पालन करना एक धर्मगुरु का पहला कर्तव्य है और यह दायित्व उस समय और अधिक बढ़ जाता है जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक पीठ या मठ की मुख्य पद पर विराजमान हो उसका मन वाणी और कर्म से धार्मिक मर्यादा के अनुकूल व्यवहार नितान्त आवश्यक ही नहीं समाज के लिए भी प्रेरक है धर्म के दस लक्षण धृति (धैर्य), क्षमा, दम (मन का संयम), अस्तेय (चोरी न करना), शौच (पवित्रता), इन्द्रियनिग्रह, धी (बुद्धि), विद्या, सत्य और अक्रोध (गुस्सा न करना) धर्म के आधार हैं लेकिन जब कोई धर्मगुरु इन लक्षणों के विपरीत व्यवहार कर सिर्फ आत्मशलाघा आत्म अहंकार आत्म प्रवंचना अथवा वेनिटी वैन के वैभव से ग्रस्त हो जाए तो असहज स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। इस बार माघ मेला प्रयागराज में यही देखने को मिला पालकी से उतर कर सिर्फ पचास कदम पैदल चलने के सादर आग्रह को भी एक विशेष पीठ पर येन-केन प्रकरेण विराजित धर्मगुरु ने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान से जोड़ लिया और पवित्र स्नान का बहिष्कार कर दस दिन तक एक राजनीतिक नेता की तरह प्रयागराज माघ मेला की पावनभूमि पर धरना दिया और फिर भाव नही मिलने पर तमाम आलोचना और अपशब्दों का प्रयोग कर बिना स्नान किए वापस लौट गए। क्या एक सनातनी धर्मगुरु से ऐसे आचरण की अपेक्षा की जा सकती है? क्या ऐसा दम्भ और अहंकार उनके मान सम्मान और गौरव के अनुकूल है? आपको बता दें कि प्रयागराज माघ मेले में पालकी पर मौनी अमावस्या स्नान से रोके जाने के विवाद के बाद अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लौटने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनसे माफी नहीं मांगी. इसे लेकर वह काफी दुखी हैं।

प्रयागराज में माघ मेले के दौरान हुए स्नान विवाद के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संगम नगरी से वापस लौटने का फैसला कर लिया है.अविमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या के पावन स्नान से मेला पुलिस ने रोक दिया था. पुलिस पर आरोप लगे कि उनके शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई. इस घटना के विरोध में शंकराचार्य बीते 10 दिनों से धरने पर बैठे थे.स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि वे अन्याय को अस्वीकार करते हैं और न्याय का इंतजार करेंगे. आज स्वर बोझिल हैं और शब्द साथ नहीं दे रहे हैं. भारी मन लेकर प्रयाग से लौटना पड़ रहा है. प्रयाग में जो घटित हुआ उसने झकझोर दिया है. मन अत्यंत व्यथित है, बिना स्नान किए यहां से विदा ले रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि न्याय की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता स्वीकार नहीं है.स्वामी अविम

संक्षिप्त खबरें

क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन को लेकर तहसील प्रशासन सक्रिय अवैध खनन कर रहे दो ट्रैक्टरों को किया गया सीज

महराजगंज रायबरेली। क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन को लेकर तहसील प्रशासन सक्रिय हो गया है। गुरुवार को क्षेत्र कलंदरगंज के पास दिन में अवैध खनन कर रहे दो ट्रैक्टरों को पुलिस नायब तहसीलदार उमेश चंद्र त्रिपाठी के आदेश पर जब्त कर लिया है। अवैध खनन की शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार उमेश चंद्र त्रिपाठी ने कोतवाली पुलिस को दिन दहाड़े खनन कर रहे दो ट्रैक्टरों को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। नाम न छापने की शर्त पर स्थानीय लोगों ने बताया कि नवोदय विद्यालय के पीछे, कलंदरगंज क्षेत्र में कई दिनों से खनन माफिया दिनदहाड़े ट्रैक्टरों और मशीनों के ज़रिये मिट्टी खनन कर रहे हैं। मामले में पुलिस अनजान बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप यह भी है कि बिना पुलिस की जानकारी के दिन में अवैध खनन करना मुमकिन नहीं है। नायब तहसीलदार उमेश चंद्र त्रिपाठी के निर्देश पर खनन में लगे ट्रैक्टरों और खुदाई करने वाली मशीन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। उपजिलाधिकारी गौतम सिंह ने बताया कि अवैध खनन कर रहे दो ट्रैक्टरों को सीज किया गया है। खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

नंदौली गाँव में 500 जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल, 8 वर्षों से जारी सेवा अभियान की ग्रामीणों ने की सराहना

लखनऊ। मोहनलालगंज के नंदौली गाँव स्थित पंचायत भवन में सरल केयर फ़ाउंडेशन ट्रस्ट, बाबू सुंदर सिंह फ़ाउंडेशन और एमडी ट्रेड लाइन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में 500 से अधिक जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। पिछले आठ वर्षों से निरंतर चल रहे इस सेवा अभियान के दौरान मुख्य अतिथि आनंद शेखर सिंह व रीना सिंह ने इसे सामाजिक जिम्मेदारी बताया, वहीं एमडी ट्रेड लाइन के प्रबंध निदेशक मुरलीधर आनंदीलाल शर्मा व ममता शर्मा ने इसे आत्मसंतोष का माध्यम कहा। सरल केयर फ़ाउंडेशन की अध्यक्ष रीता सिंह ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए भविष्य में भी सहायता जारी रखने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान रीना सिंह, डॉ. के.के. सिंह, डॉ. आलोक शुक्ला और अधिवक्ता राजेश तिवारी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ग्रामीणों ने संस्था के इस मानवीय कार्य की मुक्तकंठ से प्रशंसा की।

यूजीसी कानून के विरुद्ध स्वर्ण समाज ने राष्ट्रपति को संबोधित उप जिलाधिकारी बिसवां को सौंपा ज्ञापन

बिसवां/सीतापुर। भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी 2025 को लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) कानून को लेकर सवर्ण समाज में रोष व्याप्त है। इस संबंध में राष्ट्रपति महोदय एवं उपजिलाधिकारी बिसवां को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में यूजीसी नियमावली में कॉलेजों में जाति-आधारित भेदभाव की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल तथा इक्विटी कमेटी व इक्विटी स्क्वाड के गठन को अनिवार्य किए जाने पर आपत्ति जताई गई। ज्ञापनकर्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था योग्यता (मेरिट) के विरुद्ध है और इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के झूठे मुकदमों में फंसने की आशंका बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नियम शैक्षणिक उत्कृष्टता के बजाय जाति-आधारित राजनीति को बढ़ावा देता है, जिससे सवर्ण समाज के छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ज्ञापन में दो सप्ताह के भीतर कानून वापस न लिए जाने पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है।

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, CJI जस्टिस सूर्यकांत बोले—अगले आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (GC) द्वारा जारी किए गए नए इक्विटी नियमों (UGC Equity Regulations, 2026) पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस मामले में कोई नया आदेश नहीं दिया जाता, तब तक वर्ष 2012 के त्रुष्ट नियम ही लागू रहेंगे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दिया। GC के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया।

कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब किसी नियम की व्याख्या स्पष्ट नहीं होती, तो उसका गलत इस्तेमाल संभव है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ऐसे प्रावधानों का लागू होना गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि किसी भी नियामक व्यवस्था का उद्देश्य समानता और न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि भ्रम और विवाद को जन्म देना।

2012 के नियम रहेंगे प्रभावी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में साफ किया कि त्रुष्ट के 2012 के नियम ही फिलहाल प्रभावी रहेंगे। इसका मतलब यह है कि देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में नए इक्विटी नियमों के तहत कोई नई व्यवस्था लागू नहीं होगी।

नए नियमों को लेकर विवाद

UGC के 2026 के नए नियमों में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में इक्विटी कमेटी के गठन और भेदभाव से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए विशेष तंत्र बनाने का प्रावधान था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नियमों के कई प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इससे संस्थानों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है, साथ ही मनमानी कार्रवाई की गुंजाइश भी बनती है।

केंद्र को समिति बनाने का सुझाव

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि इन नियमों की व्यापक समीक्षा के लिए शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए, ताकि सभी पक्षों से विचार-विमर्श कर अधिक संतुलित और स्पष्ट नियम बनाए जा सकें।

अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई तक नए नियम लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक अंतरिम राहत के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही, यह आदेश सरकार और त्रुष्ट के लिए नियमों को अधिक स्पष्ट, व्यावहारिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

यूजीसी बिल का विरोध, बूथ अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

हमीरपुर :- सुमेरपुर क्षेत्र के टेढ़ा निवासी भाजपा बूथ अध्यक्ष ने मंडल अध्यक्ष पूर्वी को त्यागपत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि वह यूजीसी के लागू किए जाने से बेहद आहत है। भाजपा के टेढ़ा गांव के बूथ अध्यक्ष रोहित सिंह ने मंडल अध्यक्ष पूर्वी को भेजे इस्तीफे में स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा भाजपा को वोट दिया है लेकिन सरकार द्वारा ले गए यूजीसी से भावना आहत हुई है। हम अपने आने वाले पीढ़ी के बच्चों का भविष्य बर्बाद होते नहीं देखना चाहते हैं लिहाजा वह बूथ अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। उन्होंने अपना त्याग पत्र सोशल मीडिया में भी वायरल किया है। जिसमें लोगों ने तरह-तरह की कमेंट्स किये है। बूथ अध्यक्ष का त्याग पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्वी मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह ने बताया कि बूथ अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। उसे समझा बुझाकर पार्टी में कार्य करने को तैयार किया जा रहा है।

घर के अंदर खून से लथपथ मिला युवक का शव,आत्महत्या की आशंका

● युवक घर पर अकेले ही रहता था, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के मधुकरपुर गांव में बृहस्पतिवार को एक युवक का शव उसके घर में पड़ा मिला। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजकुमार उर्फ गुड्डू (28) पुत्र स्वा छोटेलाल घर में अकेला रहता था। उसके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। आसपास के लोग उसे खाना-पानी देते थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे पड़ोसी उसके घर पहुंचे। कमरे की फर्श पर वह चित अवस्था में खून से लथपथ पड़ा था। उसकी बाई आंख और सिर के पीछे हिस्से से खून निकल रहा था। उंगलियों में भी चोट के निशान मिले। कमरे की छत पर साड़ी लटकी हुई थी। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की बहन सुनीता, निवासी मीर मीरानपुर गांव डलमऊ की सूचना पर कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे।

विगत 6 दिनों से जारी निर्माण कार्य, कोर्ट के स्थगन के क्रम में तहसीलदार ने रोका

पीड़ित 6 दिनों से पुलिस से काम रुकवाने की लगा रहा था गुहार

महराजगंज रायबरेली। माननीय न्यायालय के स्थगन के बावजूद हो रहे निर्माण को तहसीलदार के हस्ताक्षेप पर रोका गया आपको बताते चलें कि, मामला कस्बा स्थित भूमि संख्या 254 खेवट रकबा 0. 096 जो मकसूद अली आदि के नाम दर्ज कागजात है जिसको लेकर माननीय सिविल न्यायालय द्वारा मौके पर यथा स्थिति बनाए रखे जाने संबंधी आदेश पारित किया था किंतु शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्थानीय पुलिस की मिली भगत से विपक्षी रामसुमिरन पुत्र ननकऊ लगातार विवादित भूमि पर निर्माण कर रहे हैं जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने तहसील की मुखिया तहसीलदार मंजुला मिश्रा से किया तहसीलदार ने दोनों पक्षों को तलब कर मौके पर यथा स्थिति बनाए जाने के लिए निर्देशित किया तथा कहा कि स्थगन के बावजूद अगर किसी ने निर्माण किया तो विधिक कार्यवाही की जायेगी।

अनुरक्षण की कमी से डिरेल हुआ था डीजल इंजन

● देर रात पटरी पर चढ़ाया गया, डीज़ल इंजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। क्षेत्र के चकपंचम गांव के पास किलोमीटर संख्या एमसीएफ-04 के निकट बुधवार को डीजल इंजन ट्रैक की नियमित मरम्मत की कमी के कारण डिरेल हुआ था। इंजन को पटरी में चढाने के बाद ट्रैक की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह इंजन आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना (आरेडिका) में कोच लेने जा रहा था। दोपहर 14:32 बजे अचानक इंजन पटरी से उतर गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। इंजन के डिरेल होने के बाद उसे दोबारा पटरी पर लाने के प्रयास शुरू किए गए। मौके पर रेलवे के तकनीकी कर्मचारी और अधिकारी पहुंच गए। काफी देर तक प्रयास किए गए लेकिन शुरुआती कोशिशों में सफलता नहीं मिली। इसके बाद लखनऊ से एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन को मौके पर बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद देर रात 23:21 बजे इंजन को पटरी पर चढ़ाया जा सका। इसके बाद इंजन को रात में ही लालगंज स्टेशन के आउटर पर लाया गया। अधिकारियों के अनुसार रात करीब 2:15 बजे इंजन को सुरक्षित रूप से आउटर पर खड़ा कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में इंजन के डिरेल होने का कारण ट्रैक के नियमित अनुरक्षण में कमी माना जा रहा है। ट्रैक की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। इसी वजह से इंजन पटरी से उतर गया।हालांकि विस्तृत जांच के बाद ही अंतिम कारण स्पष्ट हो सकेगा। घटना के बाद ट्रैक की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक के रखरखाव की समीक्षा भी की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। फिलहाल डिरेल हुए इंजन स्टेशन के आउटर पर खड़ा है। स्टेशन मास्टर अमित राजवंशी ने बताया कि रेल इंजन को रात 23:21 पर पटरी पर चढ़ा लिया गया। उसे स्टेशन के आउटर पर खड़ा किया गया है। उधर आरेडिका के पीआरओ अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि घटना उनके फैक्ट्री परिसर की नहीं है। इस संबंध में पता लगाया जा रहा है।

यूपी दिवस 2026 'इन्वेस्ट यूपी' स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

● निवेश के पथ पर यूपी की लंबी छलांग

विकसित भारत का आधार बनेगा उत्तर प्रदेशः वैश्य नटवर गोयल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी 'इन्वेस्ट यूपी' का स्टॉल आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। इस स्टॉल के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश के सबसे अग्रणी और आकर्षक 'इन्वेस्टमेंट हब' के रूप में प्रस्तुत किया गया। स्टॉल में राज्य की तेज़ी से बढ़ती निवेश क्षमता, मजबूत बुनियादी ढांचे और निवेश अनुकूल वातावरण को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश को विकास के नए शिखर पर ले जाना है। गोयल ने कहा, 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 'विकसित उत्तर प्रदेश' का निर्माण अनिवार्य है और यह प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से जारी है।' उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश भारत की प्रगति का एक पूर्ण विकसित स्तंभ बनेगा। उत्तर प्रदेश को देश की धड़कन बताते हुए उन्होंने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को परिवर्तन के एक जीवंत प्रतीक के रूप में सराहा। अपने संबोधन में वैश्य नटवर गोयल ने कहा उत्तर प्रदेश को 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का आईटी निर्यात 82, 000 करोड़ को पार कर चुका है और उत्तर प्रदेश तेजी से डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए 'इन्वेस्ट यूपी' स्टॉल पर निवेशकों के लिए संभावनाओं का द्वार खोला गया। यहाँ

मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश अवसरों को प्रमुखता से दर्शाया गया। साथ ही, आगंतुकों को राज्य की नीतियों, प्रोत्साहनों और निवेशक सहायता तंत्र की विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है। स्टॉल पर बड़ी संख्या में निवेशकों, उद्यमियों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं एमएसएमई निवेशकों ने भ्रमण कर इन्वेस्ट यूपी अधिकारियों से संवाद किया और परियोजना स्वीकृतियों से लेकर जमीनी क्रियान्वयन तक मिलने वाले सहयोग की जानकारी प्राप्त की। आगंतुकों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों, सिंगल विंडो पंजीकरण, निवेश प्रोत्साहनों तथा स्वीकृति प्रक्रियाओं को लेकर विशेष रुचि दिखाई।

जर्जर पुल के स्थान पर बनाए जा रहे नए पुल का निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/रायबरेली। महराजगंज-इन्हौना मार्ग पर स्थित कैर नईया नाला पर पुराने, संकरे व जर्जर पुल के स्थान पर बनाए जा रहे नए पुल का निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है, जिससे क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि, यदि कार्यदाई संस्था ने निर्माण कार्य में शीघ्रता नहीं दिखाई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों व कार्यदाई संस्था की होगी। आपको बता दें कि, कैर नईया नाला पर नए पुल का निर्माण कार्य अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था। पुराने पुल को तोड़ने के बाद चार पिलरों को खड़ा करने का कार्य प्रारंभ किया गया। प्रत्येक पिलर को 17-17 मीटर तक जमीन के अंदर स्थापित किया जाना है, लेकिन लगभग 9 माह बीत जाने के बावजूद पिलर केवल 10 मीटर तक ही गाड़े जा सके हैं। अभी प्रत्येक पिलर को सात-सात मीटर और गहराई में ले जाना शेष है। शेष गहराई तक पिलरों को गाड़ने में कार्यदाई संस्था को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साइट पर मौजूद टेक्नीशियन करन सिंह के अनुसार मिट्टी अत्यधिक चिकनी होने के कारण पिलर चारों ओर से जकड़ जा रहे हैं, जिससे वे नीचे नहीं धंस पा रहे हैं। इंजीनियर ने बताया कि, पिलरों पर 50 टन तक अतिरिक्त

भार डालने के बावजूद भी कोई खास सफलता नहीं मिली है। इस कार्य में क्रेन, जेसीबी मशीनों के साथ-साथ पानी निकालने के लिए 25 एचपी और 10 एचपी की दो मोटरें भी लगाई गई हैं, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इंजीनियर के अनुसार आगामी शुक्रवार को डी-वाटरिंग का कार्य कराया जाएगा। यदि इसके बाद भी पिलर नीचे नहीं गए तो उन पर और अधिक अतिरिक्त भार बढ़ाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि, कैर नईया नाला पुल का निर्माण कार्य अंबर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी प्रगति बेहद धीमी बताई जा रही है। इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकांत त्रिपाठी, पूर्व प्रधान राम लखन यादव, पूर्व प्रधान गंगाराम, समाजसेवी द्वारिका सिंह, डॉ. टी.पी. यादव एवं पंडित समर बहादुर पांडेय ने चेतावनी दी है कि, यदि आगामी छह माह के भीतर पुल निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कार्यदाई संस्था की होगी।

अज्ञात कारणों से तीन दुकानों में भीषण आग, लाखों रूपए का नुकसान

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के बेहटा चौराहा स्थित सरेनी रोड पर बुधवार रात तीन दुकानों में भीषण आग लग गई। आग से दो कॉस्मेटिक और एक कपड़े की दुकान पूरी तरह जल गई। दुकानों में रखा सारा सामान राख हो गया। घटना की जानकारी दुकानदारों को सुबह हुई। सूदनखेड़ा मोहल्ला निवासी कमलेश कुमारी और उनके पति छोटेलाल की अगल-बगल कॉस्मेटिक की दुकानें थीं। दोनों दुकानें टीन शेड में बनी थीं। अज्ञात कारणों से आग लग गई। सुबह राहगीरों ने धुआं उठता देखा। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक सारा सामान जल चुका था। छोटेलाल ने करीब आठ लाख रुपये के नुकसान की बात कही। आग की चपेट में बगल की कपड़े की दुकान भी आ गई। यह दुकान बेचू का पुरवा गांव निवासी संदीप पुत्र वीरेंद्र की थी। संदीप ने बताया कि दुकान में करीब दस लाख रुपये का माल था। वह कर्ज लेकर ऊनी कपड़े भरे थे। सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। दुकानदारों ने रंजिशन आग लगाए जाने की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मलिहाबाद के अटौरा में जल जीवन मिशन की खुली पोलः इंजीनियर ने कहा - 'तनख्वाह नहीं तो काम नहीं'

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद (लखनऊ): उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के मलिहाबाद विकासखंड के ग्राम अटौरा में जल जीवन मिशन योजना के तहत बनी पेयजल टंकी और पाइपलाइन की बदहाली ने ग्रामीणों का जीवन दूभर कर दिया है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए गंदे, कीचड़ भरे पानी से गुजरने को मजबूर हैं, जबकि सड़कें पाइपलाइन के रिसाव से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।ग्रामीणों के अनुसार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्थापित पानी की टंकी से जुड़ी पाइपलाइन में कई जगहों पर भारी रिसाव हो रहा है। इससे न केवल पानी की बर्बादी हो रही है, बल्कि सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं और कीचड़ फैलने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित है। खासकर स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे इस गंदे पानी से होकर गुजरते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है।ग्राम प्रधान ने इस समस्या को लेकर कई बार लिखित आवेदन संबंधित अधिकारियों को सौंपा, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना की देखभाल जिम्मेदार इंजीनियर वरुण ने प्रधान और गांव वालों से अभद्र भाषा में बात की और साफ कहा, 'मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसलिए कोई काम नहीं करूंगा। जब तक पेमेंट नहीं होगा, काम नहीं होगा। जो करना है कर लें। 'इस बयान से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कई लोग इसे सरकारी योजनाओं के प्रति लापरवाही और जिम्मेदारी से पलायन का उदाहरण मान रहे हैं। एक ग्रामीण ने बताया, 'मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का नाम तो सुना था, लेकिन यहां तो पानी की बजाय परेशानी पहुंच रही है। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? सड़कें टूट चुकी हैं, कोई सुनवाई नहीं। 'स्थानीय लोग अब उच्च अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जल निगम, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि पाइपलाइन की मरम्मत तुरंत कराई जाए, रिसाव रोका जाए, सड़कों की बहाली हो और इंजीनियर की अभद्रता पर कार्रवाई की जाए ताकि योजना का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके।यह मामला ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं की क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब मेंटेनेंस और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता से आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है।

भीषण सड़क हादसा पिता पुत्र की मौत, बाइक सवार पत्नी और तीन वर्षीय बेटा घायल, रोलर जब्त चालक फरार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। जनपद सीतापुर के थानगांव थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। रेउसा-महमूदाबाद मार्ग पर सोहलिया गांव के सामने हुए भीषण हादसे में बाइक सवार पिता और उसके मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार महेशपुर गांव निवासी लवकुश (25) पुत्र सम्बारी गुरुवार दोपहर अपनी पत्नी बीनू (23) और दो पुत्रों संगम व पीयूष के साथ बाइक से ससुराल जा रहा था। दोपहर करीब 4 बजे जैसे ही उनकी बाइक सोहलिया गांव के सामने पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक रोड रोलर से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि लवकुश और उसके 5 वर्षीय पुत्र संगम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पत्नी बीनू और छोटा पुत्र पीयूष गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद

लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानगांव पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को तत्काल सीएचसी रेउसा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया पुलिस ने दुर्घटना में शामिल रोड रोलर को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और अचानक आमने-सामने की टक्कर माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी!!

मुख्य चिकित्सा अधिकारी भदोही द्वाराएच0 डब्लू 0सी0 केंद्रो का निरीक्षण

भदोही। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भदोही डॉक्टर संतोष कुमार चक द्वाराएच0डब्लू0सी0, अभियां- का दिनांक 29.01.2026 को अपरान्ह 15.30 बजे एच0डब्लू0सी0, अभियां का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त सी0एच0ओ0 द्वारा बताया गया कि पंचायत सहायक, श्री अमरेश मौर्या, शालु पाल एवं पुजा यादव के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने में कोई भी सहयोग नही किया जा रहा है। 140 लाभार्थीयों में से 76 का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है एवं 15 मृतक है। पंचायत भवन पट्टीबेजॉव - आज दिनांक 29.01.2026 को अपरान्ह 16.10 बजे पंचायत भवन पट्टीबेजॉव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त सी0एच0ओ0 द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आज 12 आयुष्मान कार्ड बनाये गये मधु बिन्द, पंचायत सहायक के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने में सहयोग नही किया जा रहा है। एच0डब्लू0सी0, मतेथु -2- आज दिनांक 29.01.2026 को अपरान्ह 17.00 बजे एच0डब्लू0सी0, मतेथु द्वितीय- का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त सी0एच0ओ0 कु0 मोहनी वर्मा द्वारा बताया गया कि पंचायत सहायक की नियुक्ति उनके ग्राम सभा पर नही है। मोहनी वर्मा द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा था।

कमलापुर चीनी मिल में बढ़ती अनियमितताएँ, कर्मचारी असंतोष और आंदोलन की आशंका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। कमलापुर शुगर फैक्ट्री एक बार फिर आरोपों और असंतोष के कारण चर्चा में है। फैक्ट्री में कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर संगठन की ओर से प्रबंधन से वार्ता की गई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि यदि यूनिट हेड और फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो कर्मचारियों और संगठन को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। संगठन की ओर से यह भी कहा गया कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पहले ही कई स्तरों पर संवाद, निवेदन और लिखित-अलिखित प्रयास किए जा चुके हैं। इसके बावजूद यदि समस्याएँ बनी रहती हैं, तो इसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की मानी जाएगी। कमलापुर शुगर फैक्ट्री में लंबे समय से कर्मचारियों के साथ भेदभाव और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए जाते रहे हैं। स्थानीय लोगों और पूर्व से सेवारत श्रमिकों के साथ असमान व्यवहार, नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी, मेकअप स्टाफ और संविदा कर्मियों के चयन को लेकर सवाल तथा वर्षों से कार्यरत मजदूरों की अनदेखी जैसे मुद्दे लगातार सामने आते रहे हैं। आरोप है कि इनकी जगह बाहरी कर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे असंतोष की स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति श्रम कानूनों की भावना के विपरीत मानी जा रही है और सामाजिक न्याय व स्थानीय रोजगार की अवधारणा पर भी प्रभाव

डाल रही है। यह पहला अवसर नहीं है जब कमलापुर शुगर फैक्ट्री को लेकर विरोध दर्ज कराया गया हो। इससे पूर्व भी स्थानीय किसानों, श्रमिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और समाज के जागरूक नागरिकों द्वारा धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन और शिकायतें की जाती रही हैं। हालांकि, इन प्रयासों के बाद भी प्रबंधन स्तर पर ठोस सुधारात्मक कदम न उठाए जाने के कारण असंतोष बना रहा। उल्लेखनीय है कि यह शुगर फैक्ट्री एनआर इंफकॉम कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी। उस समय यह अपेक्षा की जा रही थी कि फैक्ट्री का संचालन पारदर्शी होगा, श्रमिकों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और किसानों व स्थानीय समाज के हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन फैक्ट्री के पुनः संचालन की प्रक्रिया के दौरान प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिससे इन अपेक्षाओं पर संदेह उत्पन्न हुआ है। संगठन की ओर से यह संकेत दिया गया है कि यदि समय रहते कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान, भेदभावपूर्ण नीतियों का अंत, नियमों के अनुरूप नियुक्तियाँ और श्रमिकों को उनके

संक्षिप्त खबरें

सब्जी बेचने वाली किशोरी से मनचले ने की अश्लीलता ,किशोरी ने जमकर बरसाए डंडे

हमीरपुर :- जनपद मुख्यालय में एक सब्जी बेचने वाली किशोरी ने सब्जी बेचते समय मनचले द्वारा अश्लीलता करने पर जमकर डंडे बरसाए , जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस मनचले को पकड़कर कोतवाली ले गई। हमीरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने सड़क पर सब्जी बेचने वाली एक किशोरी ने अपशब्द बोलने वाले मनचले पर डंडे बरसा दिए। सोशल मीडिया पर किशोरी के डंडे बरसाती हुई 13 सेकेंड का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि स्वतंत्र प्रभात वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मनचले को कोतवाली ले आई। वायरल वीडियो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने का है। यहां फुटपाथ पर सब्जी बेचने किशोरी के साथ एक मनचले ने छेड़खानी करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। जिससे किशोरी असहज हो गई और प्लास्टिक का डंडा लेकर मनचले पर टूट पड़ी। देखते ही देखते किशोरी ने मनचले पर जमकर डंडे बरसाए। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मनचले को उठाकर कोतवाली ले गई।वायरल वीडियो मंगलवार की रात का बताया जा रहा है।

विशाल भण्डारें में हजारों भक्तों ने छका प्रसाद

हमीरपुर :- मौदहा विकासखण्ड क्षेत्र के छिमौली गांव में कलशयात्रा के साथ शुरू हुई भागवत कथा पुराण, केवट संवाद और संत सम्मेलन गुरुवार को विशाल भण्डारे के साथ सम्पन्न हो गया इस दौरान हजारों भक्तों ने प्रसाद छका। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छिमौली में गोसाई बाबा के धाम पर लगभग तीन दशक से चला आ रहा दस दिवसीय धार्मिक आयोजन इस साल भी हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में बीते 19जनवरी को निकाली गई कलशयात्रा के साथ एक सप्ताह भागवत कथा पुराण का आयोजन किया गया जबकि 26जनवरी को धाम के नीचे से निकली चंद्रावल नदी में केवट संवाद का आयोजन किया गया। केवट संवाद के बाद शुरू हुआ निरंतर चलने वाले अखण्ड भजनो का कार्यक्रम गुरुवार तक चलता रहा और गुरुवार को हुए विशाल भण्डारे के साथ दस दिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न हुआ इस दौरान समय समय समाज सेवियों, नेताओं और वीआईपीज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का आयोजन पूरे गांव के सहयोग से किया गया जबकि ब्लॉक प्रमुख सुशीला निषाद, प्रतिनिधि लाला राम निषाद और ग्राम प्रधान सहित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मीलू निषाद सहित गांव के युवा दिनरात मेहनत करते रहे। इस दौरान क्षेत्र के हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया और सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही जबकि क्षेत्र सहित बाहर से आये संतों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष भूमिका निभाई।

माता-पिता और गुरु की सेवा से ही मिलता है यश और सम्मानः कथा व्यास लखनलाल

हमीरपुर :- सुमेरपुर विकासखण्ड के छानी खुर्द में चल रहे ग्यारह कुंडीय गायत्री महायज्ञ परिसर में आयोजित भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास पंडित लखनलाल ने माता-पिता और गुरु की महिमा का वर्णन किया।कहा कि जो व्यक्ति अपने माता-पिता और गुरु का आदर करता है, उसे संसार के सभी लोकों का सम्मान प्राप्त होता है।उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए बताया कि सेवा भाव से न केवल जीवन में यश और कीर्ति बढ़ती है, बल्कि व्यक्ति को दीर्घायु (लंबी आयु) का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कथा व्यास ने कहा कि माता हमें संस्कार देती है और पिता जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसलिए वे हमारे प्रथम गुरु हैं। धरती पर माता-पिता ही साक्षात ईश्वर के अंश हैं; उनकी उपेक्षा कर भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। सफलता का सूत्र बताते हुए कहा , यदि सच्चे मन से माता-पिता की सेवा की जाए, तो जीवन में कभी शांति और सुख-सुविधाओं की कमी नहीं रहती। कथा के दौरान भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।अंत में श्री संकट मोचन कल्याण समिति द्वारा आरती और प्रसाद वितरण किया गया।

ट्रंप का एक फैसला और कच्चे तेल में आया उबाल, क्या पट्रोल-डीजल भी होगा महंगा!

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है. ब्रेंट क्रूड 70 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जो चार महीने का उच्च स्तर है. विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर संघर्ष बढ़ा तो वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे वैश्विक तेल बाजार पर दिखने लगा है. गुरुवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जो सितंबर के बाद पहली बार है. कीमतों में यह तेज उछाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी के बाद देखा गया।

ब्रेंट और WTI में जोरदार तेजी

लंदन के बाजार में ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड 2.4% की बढ़त के साथ 70.06 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी 2.6% चढ़कर 64.82 डॉलर प्रति बैरल हो गया. जानकारों का कहना है कि अगर तनाव और बढ़ा तो कीमतों में और उछाल आ सकता है।

ईरान को लेकर ट्रंप का सख्त रुख

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत के लिए तुरंत आगे आना चाहिए. उन्होंने लिखा कि कोई भी समझौता ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई परमाणु हथियार न हों और जो सभी पक्षों के लिए सही हो. ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने बातचीत नहीं की तो हालात और गंभीर हो सकते हैं।

ईरान की पलटवार की चेतावनी

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका को साफ शब्दों में चेताया है कि अगर कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो ईरान उसका तुरंत और कड़ा जवाब देगा. इससे क्षेत्र में संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है।

तेल सप्लाई पर संकट का खतरा

मार्केट एक्सपर्ट डेरेन नाथन के मुताबिक, अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव

बढ़ता है तो ईरान के रोजाना लगभग 30 लाख बैरल तेल उत्पादन पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले तेल और गैस टैंकरों की आवाजाही भी बाधित हो सकती है. यह रास्ता दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है।

आगे और महंगा हो सकता है तेल

विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार में डर का माहौल है. जैसे-जैसे जुबानी जंग तेज हो रही है, निवेशक तेल को सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं. यही वजह है कि ब्रेंट क्रूड चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है. अगर हालात नहीं सुधरे, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है।

अज्ञात डम्पर ने आटो में मारी टक्कर, मासूम सहित तीन घायल

हमीरपुर :- मौदहा कस्बे से होकर निकले नेशनल हाईवे 34 पर डम्पर ने आटो में टक्कर मार दी जिसमे मासूम बच्चे सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिंवार थाना क्षेत्र के ग्राम लदार निवासी विष्णु (30)पुत्र चंद्र श्याम अपने परिवार के साथ आटो से मौदहा आ रहे थे तभी मौदहा के निकट नेशनल हाईवे पर अज्ञात डम्पर ने आटो में टक्कर मार दी जिसमे विष्णु, हीरामनी (25)पत्नी विष्णु और मासूम अंश (05)पुत्र विष्णु गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हे एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए कस्बे के सरकारी अस्पताल लाया गया जहां से मासूम बच्चे के गंभीर चोंटें होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है।

दिल्ली की सड़कों से बसें ग़ायब अपने मंजिल पहुंचने के लिए लोग परेशान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 15 साल पुरानी सीएनजी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के कारण सार्वजानिक परिवहन में भारी कमी आई है, जिससे यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा और भीड़भाड़ का सामना करना पड़ रहा है।सार्वजानिक परिवहन व्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही है। रोजाना लगभग 30 से 35 लाख लोग बसों से यात्रा करते हैं, लेकिन अब राजधानी में बसों की संख्या घट चुकी है। बसों की भारी कमी सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। खासकर दफ्तर के समय में बस स्टाप पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार नए रुट रेशनलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक बसों को जोड़कर स्थिति सुधारने का प्रयास कर रही है।यात्रीओ का कहना है कि पहले जहां हर 10 15 मिनट में बस आ जाती थी,अब 30 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। कमोबेश पूरी दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट

के तहत चलने वाली बसों के यही हालात हैं। लोगों का कहना है कि कई रुट पर बस आती ही नहीं जिस के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है।बस स्टाप पर खड़े यात्री ने बताया कि प्रमुख बस मार्ग जो फतेहपुरी, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रोहणी के कुतुबगढ़ गांव तक जाती है इस रूट पर भी बसे नहीं मिलती। वहीं इस बारे में डीडीसी के एमडी व परिवहन विभाग के स्पेशल कमिश्नर जितेन्द्र यादव ने कहा कि लोगों की समस्या पर हमारा पूरा ध्यान है। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करके जल्द समस्या का सामाधान कराया जाएगा।

भूमि विवाद में मां-बेटे ने खाया जहरीला पदार्थ

● युवक की मौत ,मां की हालत गम्भीर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- पुराने भूमि विवाद के चलते मां और पुत्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया ,पुत्र की हालत गम्भीर होने की वजह से उसे कानपुर रिफर कर दिया गया।पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा सुसाइड नोट। सगे चाचा द्वारा दो फीट बढ़ाकर मकान बनाने के चले आ रहे विवाद से आहत युवक ने अपनी मां संग बुधवार की रात जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे दोनों की हालत बिगड़ गई। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को कानपुर रेफर किया गया था, जहां तड़के युवक की मौत हो गई। जबकि उसकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक ने आत्महत्या करने से पूर्व डायरी में तीन पेज का लंबा-चौड़ा सुसाइट नोट भी लिखा है। जिसमें इस घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। कुरारा थाना क्षेत्र के रिठारी गांव निवासी कुंवर देवी पत्नी स्व.सूरज पाल सिंह तीन बेटों की मां है।लेकिन पति की मौत के बाद गांव छोड़कर हमीरपुर में रहने लगी। कुंवर देवी ने अपने ही देवर शिवनरेश सिंह उर्फ लालू पर उसके प्लाट में दो फीट बढ़ाकर मकान बनाने का आरोप लगाते हुए कई बार शिकायतें की थी। कुंवर देवी का पुत्र गिरधारी सिंह भी इस प्रकरण में उच्चाधिकारियों के चक्कर लगाता रहा। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। बुधवार की रात गिरधारी सिंह ने स्वयं और अपनी मां को जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे दोनों की हालत बिगड़ गई। रात में ही दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से कानपुर रेफर किया गया। गुरुवार को तड़के इलाज के दौरान गिरधारी की मौत हो गई। जबकि उसकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने से पहले गिरधारी ने डायरी में तीन पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन को ठहराया है।

सडक पर इण्टरलाकिंग की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

हमीरपुर :- मौदहा कस्बे की मुख्य सडक में मलीकुआं चौराहा से लेकर छिमौली रोड तक होने वाले हादसों से बचने के उद्देश्य से इण्टर लाकिंग की मांग उठाते हुए संगठन की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। नैशनल ह्यूमन राईट एण्ड जस्टिस मूवमेंट के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी को सम्बोधित करते हुए एक ज्ञापन तहसीलदार शिखर मिश्रा को सौंपा जिसमें कस्बे के मलीकुआं चौराहे से छिमोली रोड तक भीडभाड और पडने वाले स्कूलों के चलते बच्चों की आवाजाही के कारण सम्भावित हादसों को देखते हुए सडक के दोनों ओर इण्टर लाकिंग की मांग उठाई गई है। इतना ही नहीं संगठन ने सडक पर तेज रफ्तार चलने वाले बालू और लकडी लदे वाहनों पर भी रोक लगाने की मांग उठाई है क्योंकि इन वाहनों से अक्सर बडे हादसे होते हैं। इस दौरान डा. मुबीन खान, मुन्ना बार्डर, नईम प्रवक्ता, अरशद मामा सहित संगठन के एक दर्जन से अधिक लोग मौजूद रहे।

यूजीसी के नये नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, मोदी सरकार पर तमाचा-प्रमोद तिवारी

● राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता ने केंद्र सरकार पर सत्ता के लिए नफरत फैलाने का लगाया कड़ा आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज, प्रतापगढ़। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने यूजीसी के नए नियमों इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने के अंतरिम निर्णय को स्वागत योग्य कहा है। उन्होने कहा कि इस अंतरिम रोक से यह स्पष्ट हो गया है कि विशेषज्ञों एवं स्कालर्स की एक समिति बने और तब तक यूजीसी के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि भाजपा सरकार बांटो और राज करो की तर्ज पर अंग्रेजी हुकूमत की तरह काम कर रही है। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटकर सत्ता में बने रहना चाहती है। सासंद प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर तगड़ा तंज कसा कि इसके डीएनए में अंग्रेजों का जहर चला गया है। उन्होने कहा कि पिछले लगभग ग्यारह सालों से मोदी सरकार जाति और धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैला रही है। उन्होने कहा कि भाजपा जब से सत्ता में आयी है संविधान की शपथ लेकर संविधान की हत्या कर रही है।उन्होने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम निर्णय के बाद अब पीएम मोदी को पूरे राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण लोगों में वर्ग संघर्ष फैल गया है।कहा कि केन्द्र की बीजेपी सरकार उस सिद्धान्त को पूरी तरह भूल गयी है कि सरकार का उत्तरदायित्व है कि जहां भी अशांति हो वहां

शांति का माहौल तैयार किया जाय। सांसद प्रमोद तिवारी ने यूजीसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को देश में शांति का मार्ग प्रशस्त होने का निर्णय कहा। उन्होने यह भी कहा कि देश के मुख्य न्यायाधीश की इस निर्णय को लेकर यह टिप्पणी भी स्वागत योग्य है, जिसमें केन्द्र सरकार की नीति व नीयति पर सवालिया निशान लगाया गया है। सांसद प्रमोद तिवारी का यह बयान गुरूवार को यहां मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से निर्गत हुआ है।

विद्यालय परिसर में मरणासन्न मिली युवती, पति गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज, प्रतापगढ़। कोतवाली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय परिसर में युवती के मरणासन्न मिलने की घटना से हडकंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मरणासन्न लहूलुहान युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया। वहीं घटना की छानबीन में पुलिस पति द्वारा वारदात को अंजाम दिये जाने का दावा कर रही है। पति को गिरफ्तार कर पुलिस पूंछताछ में जुटी है।लालगंज कोतवाली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पूरे मीतन जगन्नाथपुर में गुरूवार की सुबह शिक्षक मनोज वर्मा ने विद्यालय का ताला खोला तो परिसर में एक युवती को मरणासन्न लहूलुहान पड़े देख आवाक रह गया। उसने इसकी सूचना प्रधान व पुलिस को दी। पुलिस की छानबीन में महिला के पास से मिले आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के पूरे चिरंजीव धनगढ़ गांव की निशा सरोज 22 पुत्री मेवालाल सरोज के रूप में हुई। पुलिस घायल महिला को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लालगंज ले आयी। यहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने घायल महिला को सरकारी अस्पताल प्रयागराज रेफर कर दिया। इधर घटना की छानबीन में जुटी पुलिस महिला के पति को गिरफ्तार कर पूंछताछ कर रही है। सीओ आशुतोष मिश्र ने बताया कि महिला का पति से विवाद चल रहा है। कई माह से वह मायके में रह रही थी। छानबीन में पति द्वारा घटना को अंजाम दिये जाने की बात सामने आ रही है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ईंट से हमला कर मौत के मामले में सजाः अभियुक्त को 5 साल का कठोर कारावास

बलिया। जनपद में गैर इरादतन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1 द्वारा सुनाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त राम नरेश यादव पुत्र स्व. शिव वचन यादव, निवासी तुर्तीपार, थाना उभांव, जनपद बलिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 5 मई 2022 की है। वादी की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में आरोप था कि अभियुक्त ने उनके पिता पर ईंट से हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में थाना रसड़ा में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह सजा उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ द्वारा संचालित 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की सशक्त पैरवी का परिणाम है। इस प्रकरण में अभियोजन अधिकारी एडीजीसी अनिल कुमार पाण्डेय रहे।

अभाविप सदैव से शैक्षणिक परिसरों में समता, सौहार्द एवं समान अवसरों की पक्षधर रही है

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानो में समता संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 पर स्थगन आदेश का स्वागत करती है। यह आदेश वर्तमान में देशभर में यूजीसी समता नियमों में अस्पष्टता को लेकर चल रही भ्रांति को रोकते हुए संवैधानिक समता और समानता के अंतर्निहित मूल्यों के पक्ष में महत्वपूर्ण है और यह आदेश अभाविप द्वारा उक्त विषय पर जारी वक्तव्य में यूजीसी नियमों पर स्पष्टीकरण की मांगों के भी अनुरूप है। इस विषय संबंधी वर्ष 2012 के विनियम पूर्ववत जारी रहेंगे। अभाविप का मानना है कि यूजीसी और सभी शैक्षणिक संस्थानों को लोकतंत्र की उस अंतर्निहित भावना को अक्षुण्ण रखना चाहिए, जहाँ प्रत्येक नागरिक के पास समान अधिकार हों और भारत भेदभाव मुक्त तथा समता युक्त बने। यह बात अभाविप ने अपने पूर्व वक्तव्य में भी स्पष्ट करते हुए जारी किये गए विनियम पर स्पष्टता और संतुलन बनाए रखने की मांग की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ द्वारा इस निर्णय की काफी आवश्यकता थी क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में इस विनियम को लेकर काफी भ्रांति भी फैली थी, जिससे विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य वैमनस्य पैदा होने की आशंका थी। अभाविप का यह स्पष्ट मत है कि शैक्षिक परिसर में सदैव ही सकारात्मक, भेदभावमुक्त एवं समतायुक्त परिवेश रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि, 'माननीय उच्चतम न्यायालय का यूजीसी रेगुलेशन पर स्थगन का आदेश स्वागतयोग्य है। अभाविप सदैव से शैक्षणिक परिसरों में समता, सौहार्द एवं समान अवसरों की पक्षधर रही है। यूजीसी द्वारा जारी किए गए विनियमों में स्पष्टता एवं संतुलन का अभाव छात्रों के बीच भ्रम और असंतोष को जन्म दे सकता है। न्यायालय का यह हस्तक्षेप समयोचित है और इससे संवाद व विमर्श के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। अभाविप सभी वर्गों, छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों से अपील करती है कि वे शांति, संयम और सौहार्द बनाए रखें तथा राष्ट्रहित में रचनात्मक संवाद के माध्यम से समाधान की दिशा में आगे बढ़ें।' अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री दिनेश यादव ने कहा कि, 'माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी समता विनियम, 2026 पर स्थगन का आदेश स्वागतयोग्य है। यह निर्णय शैक्षिक परिसरों में व्याप्त भ्रम को दूर करेगा और सभी वर्गों के मध्य सौहार्द बनाए रखने में सहायक होगा। '

सडक सुरक्षा जागरूकता रैली को एसपी ने दिखाई झण्डी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- सुमेरपुर फैक्ट्री एरिया स्थित जेके सीमेंट में आयोजित 37वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डा. दीक्षा शर्मा ने फैक्ट्री कर्मियों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाकर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली फैक्ट्री से चलकर इंगोहटा गांव पहुंची और वापस आकर फैक्ट्री में संपन्न हुई।37वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत गुरुवार को जेके सीमेंट में जागरूकता गोष्ठी एवं बाइक रैली का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक ने किया। जागरूकता गोष्ठी को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से जागरूकता बढ़ती है। यही कारण है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनवरी माह में हादसे कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री का यह कार्यक्रम सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम होना बेहद जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाकर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फैक्ट्री के यूनिट हेड पंकज त्रिवेदी ने सभी के प्रति आभार जताते हुए बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन समय समय पर सुरक्षा के प्रति कर्मियों को जागरूक करके नियमों का पाठ पढ़ाता रहता है। इस मौके पर प्रबंधक द्वारा फैक्ट्री कर्मियों को हेलमेट बांटे गए। जागरूकता गोष्ठी को सीओ सदर राजेश कमल, एआरटीओ अमिताभ राय ने भी संबोधित किया। इस मौके पर यातायात प्रभारी हरेंद्र सिंह, पीटीओ चंदन पांडे, प्रधान प्रतिनिधि गुरु प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह, नीरज ओझा, अविनाश, अंकित पालीवाल, विनय यादव, बाबा रंजन फरीदा, जय कुमार, अभिषेक तिवारी आदि फैक्ट्री कर्मी मौजूद रहे।

थाना सनलाइट कॉलोनी सराय काले खां पुलिस चौकी द्वारा एक सप्ताह में चोरी के 4 मामलों का खुलासा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के थाना सनलाइट कॉलोनी अंतर्गत पुलिस चौकी सराय काले खां की टीम ने एक सप्ताह के सघन और अथक प्रयासों के बाद चोरी के कई मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने चोरी के कीमती जेवरात, मोबाइल फोन और अपराध में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा भी बरामद किया है। इस कार्रवाई को क्षेत्र में सक्रिय एक संगठित चोरी गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साजिद उर्फ साहिल और फहीम के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 02 शुद्ध सोने की चूड़ियां, 01 चांदी की अंगूठी, 01 जोड़ी कान की बाली, 01 चोरी किया गया नोकिया मोबाइल फोन, 02 अन्य मोबाइल फोन जो अपराध में इस्तेमाल किए गए थे तथा 01 ऑटो रिक्शा बरामद किया है, जिसका उपयोग वारदातों को अंजाम देने में किया जाता था। पुलिस के अनुसार, इन दोनों की गिरफ्तारी से कुल चार मामलों का खुलासा हुआ है।मामलों की शुरुआत 13 जनवरी 2026 को हुई, जब श्री उमर अली ने अपने घर से 12,000 रुपये नकद चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में थाना सनलाइट कॉलोनी में ई-एफआईआर संख्या 80004159, धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद 17 जनवरी 2026 को सुश्री खुशबू ने एक सोने की चेन, एक मंगलसूत्र, तीन चांदी की अंगूठियां, 800 रुपये नकद और एक नोकिया कीपैड मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दी, जिस पर ई-एफआईआर संख्या 80005275 दर्ज की गई। तीसरी घटना 26 जनवरी 2026 को सामने आई, जब सुश्री कंचन वर्मा ने अपनी दो सोने की चूड़ियों की चोरी की शिकायत पुलिस को दी और ई-एफआईआर संख्या 80007876 दर्ज की गई।

इसके अतिरिक्त पीपी आनंद विहार आईएसबीटी, थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में एक महिला की कान की बालियों की चोरी/लूट का मामला भी सामने आया है, जिसकी पुष्टि की जा रही है।मामलों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस चौकी सराय काले खां के प्रभारी एसआई नागेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में पीएसआई दीपक, हवलदार सुरेंद्र, हवलदार वीरेंद्र, हवलदार गौरव, हवलदार रंजीत और सिपाही राकेश शामिल थे। पूरी जांच प्रक्रिया थाना सनलाइट कॉलोनी के एसएचओ श्री अशोक कुमार तथा एसीपी लाजपत नगर श्री मिहिर सकरिया की देखरेख में की गई। 17 जनवरी 2026 को ई-एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस टीम ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि पीड़िता एक ऑटो में यात्रा कर रही थी और ऑटो चालक ने पुलिस चेकिंग का हवाला देकर महिला को अपने जेवरात और सामान बैग में रखने को कहा, जिसके बाद वह सामान लेकर फरार हो गया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। सघन जांच के बाद एक संदिग्ध ऑटो (नंबर छ्रु1 ऋक्क्ङ्गङ्गङ्ग) की पहचान हुई। ऑटो मालिक पंजीकृत पते पर नहीं मिला, जिसके बाद ट्रैफिक चालान के रिकॉर्ड निकाले गए। जांच में सामने आया कि फहीम के नाम पर भारी मात्रा में ट्रैफिक चालान लंबित थे। हवलदार सुरेंद्र द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारी और टीम की तकनीकी सर्विलांस के आधार पर फहीम को बटला हाउस इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर सह-आरोपी साजिद उर्फ साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने उपरोक्त चोरी के मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली।पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी एक सुनियोजित तरीके से वारदातों को अंजाम देते थे। ऑटो चालक फहीम रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों के आसपास कम किराए का लालच देकर अकेले यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाता था। ऑटो में पीछे की सीट पर पहले से बैठा साजिद उर्फ साहिल यात्रियों को पुलिस चेकिंग का डर दिखाकर उनके जेवरात और नकदी बैग में रखने को कहता था। जैसे ही मौका मिलता,

वह बैग से कीमती सामान चोरी कर लेता था और फहीम किसी आपात स्थिति का बहाना बनाकर यात्रियों को रास्ते में उतार देता था, जिसके बाद दोनों मौके से फरार हो जाते थे।पुलिस ने अब तक थाना सनलाइट कॉलोनी के तीन ई-एफआईआर मामलों– 80004159, 80005275 और 80007876–को पूरी तरह सुलझा लिया है, जबकि थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े एक अन्य मामले की जांच जारी है। आरोपी साजिद उर्फ साहिल, उम्र 27 वर्ष, निवासी खजूरी खास, दिल्ली, पहले भी चोरी के मामलों सहित उत्तर प्रदेश में हत्या के एक मामले समेत कुल छह आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वहीं फहीम, उम्र 46 वर्ष, निवासी जनता मजदूर कॉलोनी, उत्तर